Scheduled Tribes, they were in the nature of *obiter dicta*. I understand many State Governments have already stopped observing the principle of promotions in respect of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, which in my view is unjust and illegal. I, therefore, want the Government of India to come forward with a statement today itself as it is doing in the Lok Sabha. Will the Minister of State for Parliamenary Affairs respond to this? (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): Sir, if a statement is going to be made in the Lok Sabha, I will try to persuade the Minister to make it possible to come to this House also. (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Shri Gurudas Das Gupta.

RE. STRIKE OF PILOTS

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): I would like to say just for one minute, Sir. The point is this: A persistent demand has been made in this House that the Government should take immediate steps to end the strike of the pilots. Today I have the information coming from Delhi and Calcutta that there was a meeting of the pilots and the pilots had decided that if the Government only withdrew the suspension orders and also took steps to investigate into the situation, they would withdraw the strike. This is a positive development. ... (*Interruptions*).. It should be taken up immediately and the Government should take steps to end the strike.

श्री शंकर दयाल सिंह (बिहार): मैं एक बात कहना चाहता हूं। अगर आप एक ही मेंबर को सारी बातें उठाने की इजाजत देंगे तो दूसरे सदस्यों का क्या होगा? श्री त्रिवेदी जी कल भी यह मामला उठाना चाहते थे, इसलिये आज इनको मौका मिलना चाहिये था। मैं यह नहीं मानता हूं कि एक ही सदस्य को मौका दिया जाये।

... (**व्यवधान**) ...

MR. CHAIRMAN: Please (*Interruptions*)..

श्री शंकर दयाल सिंह: ऐसी बात नहीं होनी चाहिये। ... (**व्यवधान**) ...

MR. CHAIRMAN: Please listen. If every Member has to raise his views, then the House will not function. (*Interruptions*) ...

श्री शंकर दयाल सिंह: केवल एक ही सदस्य को मौका नहीं दिया जाना चाहिये।

MR. CHAIRMAN: If you want the House to carry on its business every Member cannot raise an issue during the Zero Hour. I want to put it to the House: Do you want to go on to the business of the House or not? That is the question.

SHRI SHANKAR DAYAL SINGH: We are ready to go on to the business.

MR. CHAIRMAN: Please cooperate. Many issues have been raised already. Every Member cannot be allowed to raise an issue if you want the Appropriation Bill and the Constitution (Amendment) Bills are to go on. I will now call Shri Shantaram Potdukhe to move the motion for consideration of the Appropriation (No. 5) Bill, 1992.

THE APPROPRIATION (NO. 5) BILL, 1992

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SHANTARAM POTDUKHE): Sir, I beg to move:

[Shri Shantaram Potdkhe]

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the year 1992-93, as pased by the Lok Sabha, be taken into consideration."

Sir, the Bill arises out of Supplementary Appropriation 'charged' on the Consolidated Fund of India and Demands voted by Lok Sabha on 22-12-1992. These involve gross additional expenditure of Rs. 2,624.16 crores.

The additional requirement of Rs. 2,624.16 crores comprises Rs. 500 crores for subsidy on indigenous fertilizers, Rs. 263 crores for technical credits to foreign governments, Rs. 200 crores for arrears of cash compensatory support for exports, Rs. 110.15 crores for working capital loans to public sector undertakings, Rs. 536.06 crores for transfer to National Renewal Fund and Rs. 587.31 crores for assistance to public sector undertakings for implementation of Voluntary Retirement Schemes and Rs. 224.79 crores for service charges of International Monetary Fund, etc. The details of Supplementary Demmands are available in the Document laid on the Table of the House on 16-12-1992.

The concerned Ministries or Departments have identified matching savings or increased receipts to the extent of Rs. 1,390.79 crores. Thus, there would be a net cash outgo of Rs. 1,233.37 crores.

The question was proposed.

श्री शंकर दयाल सिंह (बिहार) : सभापति महोदय, इस समय देश एक ऐसे चौराहे पर खड़ा हुआ है जहां एक ओर प्राकृतिक विपत्तियों का हमने सामना किया और दूसरी ओर मानवों द्वारा इस तरह का संकट देश के सामने उपस्थित किया गया है, जिससे यह देश जूझ रहा है। सभापति जी, इस सदन में अच्छी तरह से इन बातों पर बहस हो चुकी है कि दक्षिण भारत में जब बाढ़ की विभिषिका से बहुत बड़ी बरबादी हुई तो उत्तर भारत में कई सूबों में सूखे और अकाल की स्थिति का भी सामना करना पड़ा है। लेकिन इससे भी जो बड़ा झंझावात इस देश में आया वह मन्दिर और मस्जिद को ले कर आया जिससे प्राचीन समय से हमारे बीच में जो सौहार्द का वातावरण था उस पर कुठाराघात हुआ है। महात्मा गांधी जी ने और देश के अन्य राष्ट्रीय नेताओं ने बहुत मुश्किल से सौहार्द का वातावरण इस देश में बनाया था और हिन्दू मुस्लिम, सिख और पारसी सबों ने मिल कर के इस देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था तथा इस देश को आजाद कराया था। राष्ट्रीय जागरण और भाईचारे का निर्माण इस देश में हुआ था। लेकिन कुछ ही दिन पहले जब हम इस तरह के झंझावत से जूझ रहे थे, देश में गरीबी पर चर्चाएं हो रही थीं, देश में औद्योगिक और कृषि विकास की चर्चाएं हो रही थीं, उसी समय एक भीषण झंझावत का सामाना देश को करना पड़ा, जिसका नतीजा यह हुआ कि कि पूरे देश में उत्तर से लेकर दक्षिण तक अनेक तरह की बातें उठीं जिनका समाना हमें करना पड़ा। इस समय मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि जब किसी पेड़ की कोई डाल टूटती है तो आवाज होती है। जब कोई भवन टूटता है तो भी एक खड़खड़ाहट होती है। हाथ से कोई कांच का प्याला छूट जाए या गिर जाए तो उससे भी आवाज होती है लेकिन आदमी का जब दिल टूटता है तो कोई आवाज नहीं होती। इस समय देश के करोड़ों लोगों का दिल टूटा है। उनके अन्दर जो भाईचारे का सिद्धांत था, उस सिद्धांत में किसी न किसी रूप में एक दीवार खड़ी कर दी गई है। ऐसे मौके पर हमारे देश के सामने मंत्री महोदय ने यह विनियोग विधेयक और सप्लीमेंटरी मांगें अनुपूरक मांगें हमारे सामने पेश की हैं। मंत्री महोदय ने जो फिगर्ज हमारे सामने प्रस्तुत की हैं, मैं केवल तीन चार बातों की ओर उनका ध्यान दिलाना चाहूंगा। मंत्री जी, जरा फिर से आप अपनी फिगर्ज की ओर देखें।

श्री पी० शिव शंकर : यह सिर्फ एप्रोप्रियेशन बिल है।

श्री शंकर दयाल सिंह : अच्छा तो एप्रोप्रियेशन बिल है। मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे सामने जो सूची आई थी डंकल प्रस्तावों पर, बहुत सी बातें कही गई थी। मैंने जैसे सुना है, यह हमारे सुनने में आया है कि डंकल प्रस्तावों के संबंध में आप सोच रहे हैं कि सदन के सब माननीय सदस्यों की राय ले रहे हैं कि एक समिति बने और काम करे लेकिन वह समिति पार्लियामेंटरी समिति गठित होगी, विचार करेगी, उसके पहले सरकार को विचार करना चाहिये कि जो आपने आर्थिक नीतियां ...(व्यवधान)

SHRI INDER KUMAR GUJRAL (Bihar): Sir, may I intervene for half a minute. My hon. friend is talking about Dunkel report which I support. The tragedy is that a delegation of the Government of India has already gone to Geneva. They are negotiating finalisation of the Dunkel report. We were given a promise in the Parliament that the issue would be discussed in the Parliament before the delegation went. Not only that, the Government had also set up Arjun Singh Committee and they had taken evidence from many of us. The Committee never came back to us to tell us or the Government as to what the Government's attitude is. Now the Government is going to commit India to a stand which the Parliament is not aware of. Therefore, I would suggest, if my hon. friend agrees that the Government should be given instructions that not only should the matter go to the Committee as he has suggested but also in the meantime our delegation should not commit itself to anything.

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): Can I say something?

MR. CHAIRMAN: Dunkel report we are going to discuss later.

श्री शंकर दयाल सिंह : सभापति जी, हम अपने मित्र श्री गुजराल जी के अनुगृहित हैं कि उन्होंने इस में कुछ कहा। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि डंकल प्रस्ताव हमारे समने विचारार्थ आया था, सभी जानते हैं कि 440 पृष्ठों का डंकल प्रस्ताव भारत सरकार के सामने विचारार्थ पड़ा हुआ है। एक बार अगर उस पर हस्ताक्षर हो जाते हैं किसी न किसी रूप में तो फिर यह संसद भी कुछ नहीं कर सकेगी मैं यह मानकर चलता हूं कि डंकल प्रस्तावों को अगर सरकार ने ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया और उस पर गम्भीरता से ध्यान नहीं दिया तो दूसरी बार हम अपने देश को बंधक रख देंगे। उससे छुड़ाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अंग्रेजों को तो हमने भगा दिया और अपने को स्वतंत्र कर दिया लेकिन इन प्रस्तावों से हम अपने आपको बंधन मुक्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए कि हमारी आर्थिक नीतियां और औद्योगिक नीतियां दोनों उसके बंधन में चली आती हैं। पिछले दिनों हमने आर्थिक नीतियां बनाई कितनी उदारवादी आर्थिक नीतियां बनाई। हमने विदेशी पूंजीपतियों को आमंत्रित किया, आप्रवासी भारतीयों को हमने आमंत्रित किया लेकिन आप्रवासी भारतीयों के नाम पर जो विदेशी पूंजी निवेश हो रहा है उसकी ओर हमने बहुत ध्यान नहीं दिया है। सभापति जी, अच्छी तरह से जानते हैं हम सभी कि जो टैंडर निकलने हैं सरकारी उपक्रमों के जैसे ओ० एन० जी० सी० का निकला कि शिड्यूल्ड कास्ट या शिड्यूल्ड ट्राइब के लिए या स्वतंत्रता सेनानियों के लिए यह लिया जाएगा लेकिन उनके नाम पर लेकर बड़े लोग व्यापार करने लगते हैं। आज आप्रवासी भारतीयों के नाम पर जो छूट हमने दी है उसका लाभ बड़े बड़े पूंजी निवेश वाले विदेशी तत्व जो हैं वे ले रहे हैं। वे एंटर करके चाहते हैं कि हम भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दें।

[श्री शंकर दयाल सिंह]

मैं तीन बातों का स्पष्टीकरण चाहता हूं जो आज ही सदन में होना चाहिए और मुख्य रुप से इसलिए होना चाहिए कि आज आखिरी दिन सदन की कार्यवाही हो रही है। पहली बात यह है कि क्या यह बात सही नहीं है कि हमारी जो आर्थिक और कृषि नीतियां आजकल बन रही है वे विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दबाव से बन रही हैं और जो कुछ उन्होंने शर्तें आपके सामने रखी हैं उनको मानकर आप चल रहे हैं? दूसरी बात, मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या यह बात सही नहीं है कि आपने जो फर्टिलाइजर सब्सिडी को कम किया, किसानों को जो सुविधाएं मिलती थीं उनको जो कम किया उसके अंतर्गत भी आपने विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों को मानते हुए ऐसा किया? निश्चित रूप से वे तत्व यह चाहते हैं कि भारत जो एक कृषि प्रधान देश है और आज जो 65 से 67 प्रतिशत लोग हमारे कृषि कार्यों में जुटे हुए हैं, आज भी भारत चावल, गन्ना, कपास, इन चीजों के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और आज भी हमारी जो कृषि क्षमता है वह विश्व के सबसे बड़े कृषि प्रधान देशों में सबसे ऊपर जाती है तो उसको हम नीचे की ओर ठेलकर ले जाएं। इसलिए मैं इन बातों को कहने की जुर्रत कर रहा हूं सभापति जी कि हम दो तरह की मार से इस समय जूझ रहे हैं। एक गरीबी की मार से क्योंकि गरीबी की जो सीमा रेखा सरकार ने तय की है उससे ऊपर हम नहीं जा पा रहे हैं और दूसरा मूल्य वृद्धि की मार से। मुद्रा-स्फीति और अन्य सारी बातों की चर्चा में इसमें नहीं करना चाहता हूं लेकिन दो चीजें ऐसी हैं, एक गरीब अपनी गरीबी से बेरोजगारी से और दूसरा गरीब तथा मध्यम वर्ग से लोग सबसे ज्यादा मूल्य वृद्धि से तबाह हो रहे हैं। आखिर इसकी जवाबदेही किसके ऊपर है यह मैं जानना चाहता हूं सरकार से। इसकी जवाबदेही पी०वी० नरसिंह राव लेंगे या इसकी जवाबदेही मनमोहन सिंह जी लेंगे या इसकी जवाबदेही के लिए हम मेजर साहब से जाकर बातचीत करें कि इसकी जवाबदेही आपकी है क्योंकि सरकार का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है, कि वह विश्वास को प्राप्त करते हुए उस जनता के लिए काम करे जिसके प्रतिनिधि के रूप से हम यहां बैठे हैं या सरकार जिसके प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। जनता के लिए जनता के द्वारा शासन जो होता है वह जनता पर भार बनकर नहीं चलता है, जनता के कष्ट को दूर करने के लिए वह होता है। इसलिए सरकार को इन बातों की ओर ध्यान देना होगा।

मेरे मित्र गुजराल साहब ने डंकल प्रस्ताव की जो बात उठाई है या मैंने जो विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो बात की है सबसे बड़ी तबाही यहां के किसानों पर उसकी पड़ी है।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : फर्टिलाइजर पालिसी यहां डिसकस ही नहीं हुई।

श्री शंकर दयाल सिंह : जबकि सभापति जी जानते हैं कि पहले दिन से हमारी कार्य-सूची में उर्वरक मूल्यों और उर्वरक पर मिलने वाली सब्सिडी के बारे में विचार करने का प्रस्ताव था, लेकिन आज तक हम उसके ऊपर विचार नहीं कर सके।

आज भी जो आप प्रस्ताव लेकर के आये हैं उर्वरकों के मामले में, पांच सौ करोड़ की सब्सिडी के लिए राशि रखी है। आज जो आपका प्रस्ताव हमारे सामने आ रहा है पांच सौ करोड़ का, लेकिन दूसरी ओर आपने सेवा-निवृत्ति के लिए जो सरकारी उपक्रमों को पैसे आप देने जा रहे हैं, वह लगभग छह सौ करोड़ की राशि है। तो आप एक ओर उनको सेवा निवृत्ति के लिए लगभग छह सौ करोड़ देने जा रहे हैं। अगर वह छह सौ करोड़ रुपये आप इसमें मिला करके, ग्यारह सौ करोड़ रुपया सब्सिडी की राशि में दे दीजिए, तो आज यहां के किसानों का कुछ भला हो जाएगा।

आज आप जो हमारे सामने ला रहे हैं, आज के दिन जो सदन से आप मंजूरी लेने जा रहे हैं, उसमें से साढ़े नौ करोड रुपये, लगभग दस करोड़ रुपये आप मंत्रियों के यात्रा भत्ते के लिए और मंत्रियों के खर्च के लिए मांगने जा रहे हैं। मंत्रियों के लिए किसलिए आप दस करोड रुपये की मांग करने जा रहे हैं? आप तीन करोड़ रुपया संसद सदस्यों के लिए नये पलेटूस के लिए मांगने जा रहे हैं। मैं पूछता हूं कि उसकी अभी क्या जरूरत है?

आपकी जो सब से बड़ी जरूरत है, उस पर पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए मैं सरकार से बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे सामने जो लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किये थे, उन लक्ष्यों से यह भटक रहे हैं और इसीलिए बार-बार इस सदन में इस बात की चर्चा की जा रही है कि सरकार की नीयत अच्छी नहीं है।

इसी क्रम में जो सब से बड़ी उदाहरण हमारे सामने है, वह प्रतिभूत घोटाले का हो रहा है और प्रतिभूत घोटाले के उदाहरण में मैं विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं इसलिए कि हमारे मित्र जगेश देसाई और सारे लोग उससे रात-दिन लगे हुए हैं। लेकिन एक बात, सभापतिजी, मैं कहना चाहता हूं जिसको सदन को बहुत गौर के साथ समझना चाहिए। अब तक यह बात मानी जाती थी कि देश के राजनेता और राजनीतिज्ञ बेईमान है, करप्ट है, लेकिन पहली बार इस देश में पूरे तौर से साबित हो गया कि देश का हमारा राजनीतिक भ्रष्ट नहीं है, हमारे व्यवसायी, हमारे अधिकारी, हमारे बड़े-बड़े, ऊंचे उपक्रमों में बैठे हुए जो चेयरमन या दूसरे लोग हैं, वह इस देश को किसी भी रूप में बेचने को तैयार हैं। यही कारण है कि आज चार हजार, पांच हजार का प्रतिभूत घोटाला, जो साबित हो चुका है' इस बात को दिखलाता है कि यहां के व्यवसाइयों ने, यहां के ऊंचे अधिकारियों ने, यहां के बड़े बैंकों ने, यहां के उपक्रमों ने, सब ने मिल कर इस देश को खोखला बना दिया है।

एक ओर आप सब्सिडी की राशि हटा रहे हैं, और दूसरी ओर आप ऐसे लोगों को तरजीह दे रहे हैं।.. (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Thirteen minutes for your party and it is over.

SHRI SHANKAR DAYAL SINGH: That is finished.

MR. CHAIRMAN: Will you conclude within one or two minutes?

SHRI SHANKAR DAYAL SINGH: Yes, within two minutes. Two minutes, Sir.

जैसा कि मैं आपको अपनी बातें बता रहा था--पहली बार इस बात का सबूत मिला है। मैं केवल तीन-चार बातों की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा।

पहली बात तो यह है कि आपने बाहर से एन.आर.आई. के नाम पर या दूसरे नाम पर अपने औद्योगिक बाजार को खोल दिया है और इस देश का दरवाजा आपने पूरी तरह से खोल दिया है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसा नहीं हो कि बाहर के लोगों के आवागमन को इस तरह खोलने से आपके अंदर का जो तत्व है, वह समाप्त हो जाए।

ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे औद्योगिक जो थे, औद्योगिक इकाइयां, वह सब की सब सफर करें और बंद हो जायें और केवल बाहर की लगने लगें। इसलिए मैं आपको यह बात कह रहा हूं कि हमारे यहां भेल, एच.इ.सी., एच.एम.टी. और दूसरे जो बड़े-बड़े उपक्रम, कोल इंडिया, सेल के जो उपक्रम हैं, उनको बराबर स्थिति को देने के लिए आप कुछ मदद नहीं करते हुए, दूसरे

[Shri Shanker Dayal Singh]

लोगों को बुला रहे हैं, जबकि गांधी जी ने बार-बार इस बात पर ध्यान दिया था और जोकि भारत की जनता को सामने रखते हुए और भारत की जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति है, उसको मद्देनजर रखते हुए गांधी जी ने बार-बार कहा था कि यहां छोटी औद्योगिक इकाइयों की जरूरत है, हमें बड़ी इकाइयों की जरूरत नहीं है। जवाहर लाल जी की नीतियां थीं कि हमारे देश में बड़ी इकाई इसलिए होनी चाहिए कि हम अपने पांव पर खड़े हो सकें और यह बात भी सही है। लेकिन ऐसा नहीं हो कि एक ओर तो आप बड़ी इकाइयों को भी बंद कर दीजिए, दूसरी ओर कुटीर उद्योग से ले करके छोटी इकाइयों को भी ध्वस्त कर दीजिए और तीसरे आपके यहां के लोग विकास के लिए तरसते रह जाएं और विकास और समृद्धि के नाम पर बाहर वालों के लिए दरवाजा खोल कर देश की अर्थ व्यवस्था, कृषि व्यवस्था पूरी तौर से चौपट न हो जाए। इसलिए बड़ी ही विनम्रता के साथ अंत में मैं सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि आपकी जो भी आर्थिक कृषिजन्य नीतियां हैं उनको स्पष्ट रूप से इस सदन के सामने आना चाहिए और उसमें कृषि को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कृषि को प्राथमिकता कि हमारा जो लक्ष्य कृषि का इस वर्ष का भी था 177 मिलियन टन का उसमें मैं समझता हूं कि 170 मिलियन ही प्रोडक्शन हुआ यानी 7 मिलियन टन का हमारा कम रहा है और यह सरकार की इस नीति के कारण है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि देश की स्वायत्तता को और देश की आर्थिक नीति को और अपने देश को वह गिरवी नहीं रखे और सरकार जिन उद्देश्यों को ले करके सामने आना चाहती है उसको स्पष्ट करे। धन्यवाद।

SHRI SANTOSH KUMAR SAHU (ORISSA): Mr. Chairman, Sir, at the outset, I stand to support the Appropriation Bill. It aims at providing Rs. 2600 crores for the supplementary Demands which can be taken from the Consolidated Fund of India.

Sir, at the beginning, while I want to speak on the Appropriation Bill, my heart throbs at the recent incident and the frenzy of fanaticism and the communal feeling and hatred which is growing in the country. I apprehend whether we are going to debase all our political maturity and the prosperity of the country.

Sir, while I was coming to this Parliament session, only two days back, I saw the sufferings of thousands of Oriya people who were working in the Surat textile mills. They had to leave everything at Surat where they were earning their livelihood. They had to flee from there. They have lost everything, and they have become beggars. They could not bring any of their belongings. They had to leave suddenly in the night. There was nothing in the station, there was nothing to provide for them. Sir, it is this human misery, this untold misery which again reminds me of the partition days. Sir, can we not rise to the occasion and feel for the people who are suffering for no fault of theirs? They are poor people who toil hard for earning their livelihood. So, at this juncture, it is high time we thought, of them and rose to the occasion to see that the country which has been marching towards progress is not ruined. And we the Members of Parliament and all the politicians have a responsibility to the country to see that again life dawns in this country rationalism comes to our thinking and we fulfill our constitutional commitment of secularism so that we can march ahead in the path of progress Let us not again think that we will go back to the age of barbarians and religious fanaticism when not only there were wars between religion and religion but even there were quarrels between different sects in one religion. And they made the bloody history of the

middle ages. Let us think of a modern world, let us think of a modern India where Swami Vivekananda and Mahatma Gandhi preached something for the upliftment of the common people, for the unity of India, India which has one of the earliest civilizations in the world, of which we are very proud. Are we going to leave it in a shambles and quarrel among ourselves? Should we not see the suffering of the common people in the communal frenzy? They have become beggars. Have we not any responsibility toward them? So, firstly I urge upon the Government that they must be sympathetic to the common people who have suffered, doesn't matter to which religion they may belong. I say of the textile workers. Thousands of them fled away from Surat because of the communal frenzy. What is their fault? They were neither involved in the Ayodhya incident nor in anything else. But they have suffered. We have to see these things in the present day world context.

My predecessor argued about many of the good points and he talked of the new economic policy of liberalisation. I am of the firm opinion that liberalisation of the economy was not only the urgent need of our country but it was in consonance with the world order today. We have to compete in the world and until we are able to stand in competition in the international order, we will be nowhere. We have to see the future of our industrialisation and our economic pattern. At the same time I also feel that there must be a feeling for the common man. How can the country develop unless we give importance to our agricultural sector? Without the development of agriculture, we will be nowhere. Here I would also urge upon the Finance Minister to see that the question of fertilizer subsidy is properly judged by the Ministry so that the poor cultivators are able to get fertilizers. That is the most important ingredient which would help our agriculture to develop. I say with all the strength at my command that the subsidy which was introduced must benefit the poor pepple. But these benefits do not reach the common agriculturist. It is strange that it is utilised for some other purpose and the poor agriculturist who is toiling hard in the fields, who is the backbone of our economy in the development of agriculture, does not get the benefit. Without development of agriculture, there can be no solution to our economic problems. But the poor man is not getting these benefits. I earnestly urge upon the Government to ensure that the poor cultivator who is toiling hard, must get the benefits. India was able to build up an image for itself due to our green revolution. But all these things have now come to a standstill. Though some States have developed in agriculture, some others, particularly the Eastern States have suffered. We have to go into the genesis of it and see how these States also are able to achieve this development in agriculture.

Coming to another point, there is vast unemployment, particularly among the educated youth. The rise in unemployment among the educated youth has created a sense of frustration which is suicidal in the development of our country. Whatever be the Government at the Centre or in the States, they must look into the problem of unemployment. The educated youth of this country have lost their mission; they have become frustrated; they have become angry. We have to see that there develops a social cohesion. For that, we have to plan in such a way that we have job-oriented system of education so that we are able to utilise our educated youth in the constructive work for the nation, without which probably we may fail in our mission and we may not be able to fulfil our objective and we may witness all rowdyism and violence and such other activities. Many years ago we thought of connecting Ganga and Cauvery in one national grid. That scheme could imbide a

[Shri Santosh Kumar Sahu]

spirit of national feeling among our youth. As in many other countries, some of the voluntary orgaisations could also be involved. We have to create a new horizon without which probably we are losing that kind of national feeling in the country and we find the youth today frustrated and angry which may create a havoc for the country. I urge upon the Finance Ministry and the Planning Ministry to consider these things as to how a national spirit can be imbibed in our youth and how we can have work-oriented programmes. For that, we may even have to sacrifice some of our projects.

We are fortunate to have a immense wealth of natural resources and raw material, but natural calamities have been visiting us year after year. They have created a havoc in some parts of the country for which we have to make a national programme so that we are able to reduce the impact of these vagaries of nature to the minimum and save our people from suffering. We have to have some national schemes. Such a scheme can create a new urge, a new mission and a new spirit among our people. We have to forget the barriers of language, the barriers of region, the barriers of religion and forget many other things. But this type of approach is lacking in our planning.

I come from a village area. We know the conditions of our financial institutions. We have to go into the genesis of the problem to find out how these financial institutions are losing their liquidity. In the rural areas, it is very difficult for the entrepreneurs to get small loans from these institutions. First, was the waiver of the loans; then came the scam and now we find ourselves completely at a dead end. The financial market is so tight. I think we need to have some emergency programmes for the financial institutions so that they are able to help the small man, the agriculturist who is the worst hit. The small entrepreneur would be the worst hit. Then, how can we think of the younger generation rising to the occasion? Therefore, we have to evolve a new system. It is true that some tragedy has befallen us. But the tragedy has to be countered, has to be checked, has to be overcome. We should see that the agriculturists in the villages, the poor people in the villages, the small entrepreneurs, do not suffer. They must get financial assistance. This is very important.

We are now talking of attracting the NRIs. We are talking of the liberalisation of the economy. In this connection, I would urge upon the hon. Finance Minister and the hon. Prime Minister. I would draw their attention to the fate of a particular project. As you know, for Orissa annd Karnataka, two steel plants were promised long back. A decision in this regard was taken by the Cabinet then. Now, we have this resource crunch. This project has remained on paper for decades. Why don't we make use of the liberalisation policy for this purpose? We can give customs duty concessions in regard to equipment and materials brought into our country. We can give such facilities so that we would be able to attract foreign collaboration for this project. It could be a joint venture between the Government of India and the other. This would help our youth getting employment. This is very important. Otherwise, the number of unemployed youth would further increase. In the end, the youth of our country would become totally frustrated. Only when we create new employment opportunities, prosperity can come to our people, to the country. We have to give importance to these small but important things.

In this Appropriation Bill, I find that money has been asked for towards subsidy on fertiliser. I would

urge upon the Government to appoint a committee, to see that the subsidy given by the Government does not go to others, but reaches the common cultivator, the poor farmer, the poor agriculturist, in the village, for whom it is meant. Otherwise, the large amount of subsidy we are giving, along with the dual pricing policy, would not be of any help to them.

In this connection, I would bring to the attention of the Government the difficulties of the farmers in my State. I belong to Orissa which, as you know, is a backward State. The quantity of fertiliser promised by the fertiliser department has not reached our people till date. We have written many letters. I do not know what is the policy. The Government must see that the agriculturists do not suffer, under any circumstances.

I would also take this opportunity to appeal to the leaders of all the political parties. We must think of a new national order. We must think of new ideas. We must forget the communal frenzy. We must forget religious wars. We must abide by our Constitution. We must think of building a new, modern, India. Sir, India has achieved many things in the last forty-five years. We are the eighth industrial nation in the world. We are the third in terms of scientific and technical personnel. But what we are lacking is the combining force. We need the combining force of unity. We have to strengthen it.

We must forget our caste, communal and other differences. How long can we go on like this? Sometimes, we must forget these things. The national goals must be given the highest priority. Political considerations should be left behind. It is high time that all of us put our heads together. The Government should seek the co-operation of like-minded people so that we can build a modern, prosperous, India. We should keep the communal frenzy in check. We should rise above communal and caste considerations. Then only we can go ahead. Otherwise, these things would destroy us. The whole national fabric would be destroyed because of this.

As I said, when we are thinking of liberalisation, we must also think of agricultural development. We must also think of the development of small-scale industries. We should not forget what Mahatma Gandhi said. We should not forget the thousands of people living in the villages, underfed, underemployed, below the poverty line and without much economic support. We should try to develop the small scale industries. The Khadi Board has to play a vital role. Then there is the cottage industry. These are the mass employment-originating sectors. They must give all the facilities. Probably we have forgotten all these things. We have started thinking of liberalisation and other things, but we do not see what is happening in other countries. There is recession. America is under recession. Probably, the conditions leading to unemployment there have created problems for their society. So, we have to take stock of the things happening in our own country. We must see how new employment opportunities can be generated not only for the village people but also for the educated youth. There are young people who are unemployed even after getting technical education. They are not getting jobs. So, you must create new employment opportunities through different new type of industries. You must coordinate and have new financial schemes.

With these few words I would like to support this Appropriation Bill. We have no alternative but to see that the Consolidated Fund takes into consideration all these things. You should create conditons which will give new hopes. You have to take up all these issues to build a new India.

श्री रामबास अग्रवाल (राजस्थान) : अध्यक्ष महोदय, अयोध्या कांड के बाद हर बार समाचार-पत्रों में पढ़ने को मिलता है कि सरकार और प्रधान मंत्री आहत हैं, घायल हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह अधमरी सरकार अब विनियोग विधेयक किस के लिए रख रही है क्योंकि जिस सरकार में लोग आहत हैं घायल हैं, मानसिक संतुलन नहीं हैं, उनको इस प्रकार के विनियोग विधेयक लाने का अधिकार नहीं है और यह सरकार भी अब कितने दिन चलेगी, इसका भी कोई भरोसा नहीं है? तो

[उपसभापति महोदया पीठासीन हुईं]

इस हालत में इस विनियोग विधेयक पर संसद में विचार करना चाहिए कि वापिस भेज दिया जाए? इसका कोई अर्थ नहीं है।

महोदया, मैं एक बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारी वर्तमान केंद्रीय सरकार ने आर्थिक नीतियों में बड़ा भारी परिवर्तन किया था और यह कहा था कि वे बड़ी लम्बी उड़ानें भरने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। समाजवादी घुटन से उन्होंने मुक्ति पाई, देश को भी मुक्ति दी और हमने, भारतीय जनता पार्टी ने, उनके कुछ विचारों का समर्थन किया आर्थिक दृष्टि से। लेकिन, महोदया, मैं जानना चाहता हूं कि जब यह विनियोग विधेयक सरकार ने रखा है तो आज उनको एक बात का स्पष्टीकरण इस देश को देना होगा और वह बड़ा महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण होना चाहिए कि इस सरकार ने जो आर्थिक नीतियां रखी हैं, वे कांग्रेस पार्टी की अपनी नीतियां तो नहीं थीं, उनको कुछ दलों का समर्थन प्राप्त था। ... **(व्यवधान)** ...

एक माननीय सदस्य : आपका।

श्री रामदास अग्रवाल : कुछ दलों का मैं कह रहा हूं। मैं पहले बोल चुका हूं कि हमने उनकी कुछ नीतियों का समर्थन किया था लेकिन अब इस सरकार के पास अपने आपको बचाने के लिए, आज भी प्रधान मंत्री जी का वक्तव्य अखबारों में पढ़ने को मिला, कल जो उन्होंने अपनी पार्टी के संसद् सदस्यों को दिया, उन्होंने कहा है कि हमें वामपंथी दलों का सहारा चाहिए। महोदया, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सरकार की नीति, जो खुलेपन की नीति है, क्या इसका वामपंथी दलों ने समर्थन किया है या वह नीतियों में परिवर्तन करने जा रहे हैं? यह बात आज अंतर्राष्ट्रीय जगत जानना चाहेगा। **(व्यवधान)** जरा शांति रखें क्योंकि अभी तो आपके बहुत सारे काम और बातें सामने आने वाली हैं। ... **(व्यवधान)**

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव (महाराष्ट्र) : कांग्रेस को किसी का सहारा नहीं चाहिए, उसको सहयोग चाहिए।

श्री रामदास अग्रवाल : मैं अपने शब्द नहीं बोल रहा हूं, प्रधान मंत्री महोदय के शब्द कह रहा हूं, जो उन्होंने कल कहे हैं आपकी संसदीय पार्टी में। महोदया, आज हम लोग यह कहने जा रहे थे, दुनियां के लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं कि हमने अपनी उन्मुक्त आर्थिक व्यवस्था की रचना की है। लेकिन जिस सरकार ने उन्मुक्त आर्थिक रचना की व्यवस्था की, आज वह सरकार लड़खड़ा रही है। आज उसको अपने ही कदमों पर शक हो रहा है। तो ऐसी हालत में उन्हें दुनियां को यह बताना पड़ेगा, इस संसद को बताना पड़ेगा कि उनके सहयोगी जो आज उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आपको बचाने के लिए चल रहे हैं, केंद्र सरकार को बचा रहे हैं, कांग्रस की सरकार को बचा रहे हैं वे क्या उन नीतियों का समर्थन कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो हमारे वामपंथी दल या बाकी के लोग जो उनका समर्थन करते हैं तो वह छाती ठोककर खड़े होकर कहें कि—हां, हमने कांग्रेस को बचाया है और उसकी आर्थिक नीतियों का भी समर्थन करते हैं। उन्हें यह कहना चाहिए। हमने कहा था। आप सरकार में थे, हम विपक्ष में थे लेकिन हमने उन्मुक्त नीतियों का समर्थन

किया था और हमने खुले तौर पर किया था । कुछ लोगों ने आरोप लगाया था कि हम सरकार के साथ मिले हुए हैं । क्या मैं आज यह आरोप लगा सकता हूं कि वामपंथी दल आज अपने स्वार्थों के कारण कांग्रेस के साथ मिल गए हैं और फिर कहते हैं कि वे आर्थिक नीतियों का समर्थन नहीं करते । आज अगर वह यह कहना चाहे तो कहें कि आर्थिक नीतियों का समर्थन करते हैं, कांग्रेस के समर्थन में मुझे कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन उनको कहना चाहिए, खुले तौर पर कहना चाहिए । यह दगा नहीं चलेगा देश के साथ, यह दोमुंही बात देश के साथ नहीं चल सकती । कम्युनिस्टों ने हमेशा दोमुंही बात की है और जब आवश्यकता पड़ी इस देश की राजनीति को तो विपक्ष की राजनीति को धोखा दिया है । महोदया, इसलिए, मैं कहना चाहता हूं कि उनको भी यह बात कहनी चाहिए . . . (व्यवधान)

SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJI RAO SHINDE (Maharashra): I am on a point of order.

उपसभापति . पोइंट आफ आर्डर, बोलिए, क्या पोइंट आफ आर्डर है ।

SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: Whether the discussion going on is on an Appropriation Bill or a political Bill, that should be explained.

SHRI KAMAL MORARKA (RAJASTHAN): Under the Appropriation Bill we can discuss anything.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Under the Appropriation Bill you can speak on appropriation and you can also speak on misappropriation!

श्री रामदास अग्रवाल : महोदया. मैं केवल आर्थिक नीतियों की चर्चा कर रहा हूं इसलिए आप चिंतित न हों । मैं अयोध्या की चर्चा नहीं करूंगा । लेकिन आर्थिक नीतियों में जो एक मूलभूत बात है उसकी अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो इसका महत्व कम हो जाएगा । इसलिए मैंने यह विषय छेड़ा है कि मंत्री महोदय और वामपंथी दल यह स्पष्ट घोषणा करें कि वह भी उनकी आर्थिक नीतियों का समर्थन करते हैं । यही मेरा एक पोइंट है और इसके अलावा इस मामले में मेरा कोई दूसरा पोइंट नहीं है ।

प्रो० सौरीन भट्टाचार्य (पश्चिमी बंगाल) : . . . (**व्यवधान**) क्योंकि प्रधान मंत्री की ओर से बोला जाएगा । अब वामपंथी का जो प्रोग्राम है वही मान लेते हैं ।

श्री रामदास अग्रवाल : आप अपनी कांग्रेस से मनवाइए अपने प्रोग्राम, हमको इसमें कोई आपत्ति नहीं है । अगर वह मानें तो बहुत अच्छी बात है । उन्मुक्त आर्थिक रचना के विचार को छोड़दें अगर कांग्रेस के लोग छोड़ना चाहें तो ।

महोदया, मैं एक दूसरे विषय की ओर आना चाहता हूं । यह एप्रोप्रिएशन बिल तो आया है लेकिन मिस-एप्रोप्रिएशन का कोई हिसाब नहीं आया है । अभी तक इन्होंने . . . (**व्यवधान**)

श्री विठ्ठल राव माधवराव जाधव : . . . (**व्यवधान**) आपने कर दिया पूरा । . . . (**व्यवधान**)

श्री रामदास अग्रवाल : मैं तो अभी आपके आर्थिक रचनाओं के मिस-एप्रोप्रिएशन की बात कर रहा हूं, श्रीमान, देश की छोड़ दीजिए आप । अभी तो आर्थिक रचना पर विचार कर रहे हैं ।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : आपको तो राम ही बचाए ।

श्री रामदास अग्रवाल : हम को तो राम ही बचाएगा, आपको रावण थोड़ी बचाने आएगा ।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : अगर राम के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं . . (**व्यवधान**)

श्री रामदास अग्रवाल : आप अगर राम और रावण की चर्चा करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, स्वागत है आपका । मैं उसके लिए तैयार हूं ।

महोदया, इस सरकार के समय में जो मिस-एप्रोप्रिएशन हुए हैं, उनके उदाहरण दुनियां में देखने को नहीं मिलते । इस सरकार के हमारे महानुभाव अपना यह विनियोग विधेयक तो लाए हैं लेकिन सरकारी उद्योगों के शेयर्स के बेचने में जो घोटाला हुआ है, उसके बारे में वे कुछ कह सकते थे । इस देश की जनता को उसके बारे में उन्हें जवाब देना चाहिए कि आखिर, हजारों-करोड़ों रुपये के शेयर्स आपने बेचे हैं, उसमें कितना घोटाला हुआ, कितना गड़बड़ हुआ, कितना भ्रष्टाचार हुआ, कितने लोगों ने अपने घर भरे, इसकी कुछ जानकारी तो दें, आखिर, इस देश में यह सब कैसे चलेगा अगर सरकारी उद्योगों की सम्पत्ति को बेचा जा रहा है तो उनको कम कीमत पर बेचा जा रहा है, उसका आकलन कम किया जा रहा है, उसका मार्केट रेट कम लग रहा है। यह सब क्या हो रहा है इस देश के अंदर ? आखिर, यह देश इस बात को जानना चाहता है ? हमारे कांग्रेस के भाई, नेतागण अगर यहां समझते हैं कि इस देश के लोगों को गुमराह किया जाता है तो मैं समझता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती पर हैं । वे केवल यह कहकर नहीं बच सकते कि है बैक स्कैम तो पड़ा है—जे० पी०सी० में और सरकारी उद्योगों के शेयर्स बेचने में जो गड़बड़ी हुई है उसके बारे में वह जांच कर रहे हैं । यह जांच कब तक चलती रहेगी ?

आखिर इन उद्योगों के अंदर लगी हुई संपत्ति हमारे देश के लोगों की संपत्ति थी और उस संपत्ति के बारे में जानने का हमें पूरा अधिकार है । मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि वह कम से कम इस बात की जानकारी दे इस सदन को कि जितने शेयर बेचे गए उनमें किस प्रकार के कितने घोटाले किन-किन लोगों ने किए और शेयर्स बेचने में गड़बड़ियां क्या-क्या हुई । उस बारे में इस सदन को जानकारी देकर अवगत करें ।

महोदया, मैं एक दूसरा सवाल और उठाना चाहता हूं । वर्तमान सरकार में बैठे हुए जो महानुभाव हैं वे पानी पीकर बार-बार यह कहा करते थे कि वे गरीबों के मसीहा हैं, वे बेरोजगारों को रोजगार देना चाहते हैं, वे किसानों को और सस्ती दरों पर सब चीजें उपलब्ध कराना चाहते हैं । वे किसानों के मसीहा थे, वे उद्योगपतियों के मसीहा थे, वे बेरोजगारों के मसीहा थे, गरीबों के मसीहा थे लेकिन आज इनका चेहरा उजागर हो गया है । आज इनके चेहरे पर से नकाब उठ गई है । ये लोग आज गरीबों के प्रति उदासीन हैं । आज एन० आर० आई० की चिंता सरकार कर रही है, आज मल्टी नेशनल कंपनीज की चिंता यह सरकार कर रही है लेकिन इस सरकार को अपने गरीब किसानों की कोई चिंता नहीं है जिनकी सब्सिडी विदड्रा कर ली गई । किसान को जो सब्सिडी दी गई थी वह वापस लेकर उस किसान को सबसे ज्यादा संकट में इस कांग्रेस सरकार ने डाला है ।

महोदया, आज का किसान प्रताड़ित अनुभव करता है । वह अपनी उपज को अधिक दाम पर बेच नहीं पाएगा, उसकी कास्ट बढ़ जाएगी । ऐसी स्थिति में वह किस प्रकार से अपना जीवन-यापन कर सकेगा यह महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने खड़ा है । महोदया, किसान को जो सब्सिडी पहले दी जाती थी वह बहाल की जानी चाहिए और किसानों को सस्ती दरों पर खाद उपलब्ध कराने के लिए आने वाले सीजन में पूरी तरह से मदद दी जाए । यह मेरी सरकार से मांग है और मैं यह चाहता हूं कि सरकार किसानों को सब तरफ से मदद करने के लिए तैयार खड़ी हो ।

महोदया, एक विषय और मैं आपके सामने लाना चाहता हूं । आपको याद होगा, मैंने पहले भी कई बार संसद में यह बात कही थी कि बैंकों ने जो छोटे-

छोटे उद्योगपतियों को, छोटे-छोटे कारखाने के लोगों को, छोटे-छोटे निर्यातकों को सब प्रकार की जो सुविधायें पहले दे रखी थीं, वह उन्होंने बंद कर दी हैं। आजकल अगर कोई आदमी बैंक गारंटी मांगने जाता है तो उससे कहा जाता है कि पूरा रुपया जमा कराओ तब बैंक गारंटी दी जाएगी। उसको अगर लैटरआफ क्रेडिट खोलना है तो उसको पूरा रुपया जमा कराना पड़ेगा। उद्योग-धंधा लगाना है तो 80 परसेंट की सिक्योरिटी और देनी पड़ेगी ऐडीशनल, तब जाकर वह उद्योग लगा सकता है। अर्थात् अगर उसके पास सौ परसेंट पैसा हो तो वह उद्योग लगा सकता है। इस प्रकार की परिस्थिति हमारी सरकार के बजट के बाद हो गई है। सारे बैंकों ने इन छोटे-छोटे उद्योग-पतियों और छोटे-छोटे लोगों के प्रति इस प्रकार का दुर्भावनापूर्ण व्यवहार शुरू कर दिया है जिसके कारण ऐसा लगता है कि छोटे उद्योग एकदम समाप्त हो जाएंगे। इनका अस्तित्व भी रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि यह जो छोटे-छोटे लोगों को गारंटी खोलने के लिए भी बैंकों में दौड़ना पड़ता है और कैश देना पड़ता है, यह स्थिति वास्तविक है। सरकार को इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मेरी सरकार से मांग है आखिर यह कदम क्यों नहीं उठाती इन छोटे उद्योगों को संरक्षण देने के लिए?

हम दुनिया भर के अंदर जाते हैं, बात करते हैं लेकिन इन छोटे-छोटे उद्योगों के बारे में कोई चिंता करने वाला व्यक्ति आज इस देश में दिखाई नहीं देता है। बेरोजगारों की संख्या भी इस देश के अंदर बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। आज बेरोजगारों को नौकरी देना तो दूर रहा लेकिन जो लोग सरकारी उद्योगों में या अन्य जगहों पर काम करते थे, जो भी उनका उद्योग या रोजगार था वह भी छिनने की स्थिति में आ गया है। महोदया, बेरोजगारी पहले से मौजूद है, रोजगार छिन रहा है, ऐसी स्थिति में क्या कांग्रेस के लोग ऐसा समझते हैं कि बेरोजगारों की इतनी बड़ी फौज को इकट्ठा करके क्या इस देश के आर्थिक तंत्र को वे एन०आर०आई० और मल्टी नेशनल कंपनीज के आधार पर चला सकेंगे? यह आश्चर्य की बात है। हम चला सकते हैं ऐसा वे सोचते हैं तो यह केवल दिवास्वप्न है। यह केवल हमारे सोचने का गलत दृष्टिकोण है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम दुनिया से मदद लें, उससे हमें आपत्ति नहीं है लेकिन कम से कम दुनिया से मदद के साथ-साथ यहां का छोटा उद्योगपति है, छोटा कारखाने का मालिक है, छोटा व्यापारी है, नवयुवक है जो रोजगार ढूंढता है उसको हम रोजगार तो उपलब्ध कराएं तब जाकर पता लगेगा कि हम वास्तविकता में भारतवर्ष का कल्याण करना चाहते हैं।

महोदया, सरकार ने यह वायदा किया था इस संसद से कि वह खर्चों में कटौती करेगी। सरकारी खर्चे में कितनी कटौती की गई है सरकारी उद्योग धंधों में कितनी कटौती की गई है? सरकार के ऐडमिनिस्ट्रेशन में कितनी कटौती की गई है सरकार के यात्रा भत्तों में कितनी कटौती की गई है। सरकारी अफसरों के पांच सितारा होटलों में मौज मस्ती उड़ाने पर जो खर्चा होता है उसमें कितनी कटौती की गई है? सरकार ने विदेश यात्रा में कितनी कटौती की है? कौन से क्षेत्र में जहां कटौती की गई है, यह सरकार इस सदन को बताए। आपने कहा कि कटौती करेंगे। आप ऐडीशनल खर्चे करते जा रहे हैं, ऐडीशनल फंडस मांगने जा रहे हैं लेकिन इस देश को आप जानकारी नहीं दे रहे हैं कि सरकार के खर्चों में कटौती क्यों नहीं हो रही है। सरकार खर्चे कम करने की मंशा नहीं रखती। आप अपने बजट को किस प्रकार नियंत्रित करेंगे, बजट में जो कटौती करने का जो आपने वायदा किया था उसमें क्यों कमी नहीं हुई, इस बारे में सदन को बताएं।

अंत में, महोदया, जो आपने मुझे अवसर दिया उसमें अपनी बात को भी कंक्लुड करते हुए मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जैसे मैंने प्रारंभ में यहां पर निवेदन किया, सरकार इस बात का आश्वासन दे कि उनकी आर्थिक नीतियां वही चलती रहेंगी चाहे उनके

[श्री रामदास अग्रवाल]

वामपंथी सहयोगी उनके साथ रहें या नहीं, यह वायदा आपको देश को देना होगा और अंतर्राष्ट्रीय जगत को देना होगा अन्यथा गलतफहमियां फैलती रहेंगी और जो लोग यहां आना चाहते हैं, यहां पर पैसा लगाना चाहते हैं वह नहीं लगाएंगे। आपके वामपंथी इस प्रकार से उन्मुक्त अर्थ व्यवस्था का सपोर्ट नहीं कर सकते। इसलिए यहां का आर्थिक ढांचा फिर बिगड़ जाएगा। इसके लिए आपको देश को आश्वस्त करना होगा और दुनिया को आश्वस्त करना होगा।

महोदया, दूसरी मेरी मांग यह है कि गरीब लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए और किसानों को सहायता देने के लिए जो सबसिडी आपने किसानों की खत्म की है, उसको आप बहाल करें।

यही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपने जो मुझे अवसर दिया है उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

SHRI ASHIS SEN (West Bengal): Madam Deputy Chairman, I thank you for giving me this opportunity to speak on the Appropriation (No. 5) Bill, 1992. I stand to oppose this Bill from every angle because this Government has got no right to ask for more funds to carry forward its anti-people, anti-national, economic and industrial policies.

Incidentally I was keenly hearing what Mr. Ramdas Agarwal of the BJP was speaking little earlier. Is he the representative of the same BJP which has all along supported the economic and industrial policies of the Government, who is now coming forward to say something differently that Left forces are supporting the Congress party to carry on its activities? I completely deny this proposition. Either he has been looking at the things with a myopic eye or that he is deliberately trying to mislead the people that there has been a co-relation and collaboration between the Left forces and the Congress party. Yes, we did support this Government on a specific issue because a set of people in the name of fundamentalism, in the name of Hindutva were dragging the country into a holocaust. We supported them because this has got to be stopped. If any force, whether the Government or anybody else, comes forward to prevent this position, we from our side, the Left forces will positively and all along support it but not with a dual voice like the BJP who supported the Government on economic and industrial policies and come over here to say that there has been some link between the Left forces and the Congress party. I strongly condemn this attitued and the stand.

Mr. Agarwal also spoke about the need for bringing in more foreign funds. He has no objection to borrow loans from the IMF and the World Bank which by itself will carry the country to a situation where the entire interests and the prestige of our country are going to be mortgaged. He has got no opposition for such funds coming in. I oppose this stand. But he wants to....

श्री रामदास अग्रवाल : महोदया, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि मैंने आई०एम०एफ० या वर्ल्ड बैंक से लोन लेने की बात कही है, वह मैंने अपने वक्तव्य में नहीं कहा है। मैंने कहा है कि मल्टीनेशनल कंपनीज या बाकी क्षेत्रों से हमें यदि आर्थिक सहायता मिलती है तो उसका स्वागत है। लोन शब्द मैंने काम में नहीं लिया है।

SHRI ASHIS SEN: Madam, it does not make any difference, whether the money is coming from the multinationals or by way of dakshina from others. . it makes no difference. Anyway, I am thankful to him because he has tried to take note of it, confirming what I have said earlier.

I oppose this from all angles because the Government has failed in every respect. Let us look at food and agriculture. What is the position? An assurance was given at the time of the last Budget that thousands of fair-price shops would be opened throughout the country so that the prices might come down. What do we

find today? Did it happen? No. What has been the position in the procurement of food? It has not been that much. And that fair-price shops are to be opened in different parts of the country and in the villages has been more in the nature of a talk than a reality. They failed in procurement. Not only that. In places like the State of West Bengal, from where we come, every effort is being made to run the fair-price shops and ration shops efficiently. The essential requirements of the public distribution system are to be supplied by the Centre. But, deliberately or otherwise, the centre have cut the supply drastically so that the West Bengal Government may not be able to run the public distribution system. To that extent, the people in the black market get an opportunity to raise the prices of essential commodities.

What do you find in the field of agriculture? And what about subsidy? What is the position in regard to subsidy for fertilizers? Not only fertilizer prices are being raised, but multi-national fertilizer corporations are being allowed to come in and public-sector fertilizer corporations are asked to compete with them. Withdraw subsidy for national, indigenous, industries and ask foreign concerns, with a larger subsidy to them in various ways, imports, exports and customs duty — I mean liberalisation —to come in! That is their line.

I come to the question of budgetary provisions. Budgetary provisions were there to provide funds to the public-sector undertakings, including fertilizer units. But what is the position today? Budegtary grants are not being given to them with the result that they are not being able even to pay salaries to their staff. In some public sector undertaokings, the staff are not getting their salaries for months or they get their salaries much delayed. Even in the matter of purchase of raw materials, public industries are suffering for want of budgetary grants in time. What is the position of employment? Has there been any improvement? Has there been any employment generation because of the New Industrial Policy or there has been more unemployment created? The Exit Policy has been there. Millions of dollars are being borrowed from international agencies to create conditons for workers to get out of their jobs. Is it in national interest? Is it in the interest of the people of the country? Or, is it an anti-national move that is being pursued by the Government against the common man against the wage-earner? What is the position of industrial growth? So much of funds is moving around in the stock exchanges. But how many new industries have been created? How much of expansion has taken place in the matter of the existing industry? Is there any answer? Can the Government tell the people that they have done something for the industrial growth and the generation of employment? In every respect, be it prices or housing or whatever, we find that the Government has failed. It has failed on every count. They are not interested in seeing that the common man's interests are served because they are to serve the interests of the big business at the dictates from foreign loan giving agencies, the dictates of the World Bank and the Inter-national Monetary Fund. What is the position of the balance of payments? There was an economic research. The researchers have pointed out that the estimate of the Bop in the coming years will continue to be negative as the imports are put in the region of 33.5 bilion dollars and the exports, 27.5 billion dollars. There is a gap of six billion dollars. How to amke up? Borrow, borrow more to pay for the dues of the earlier loan. Is it the manner in which the economy of this country is going to be served? And for that matter, the Government wants to appropriate funds or misappriate funds from the public exchequer. What is the position of indebtedness? It is 2 lakh crores of rupees in terms of Indian money. Even for that whatever foreign loan has been taken for specific purposes, though they obtained it, still we find one-third of that loan, that s about Rs.

[Shri Ashish Sen]

35,000 crores or more, has remained unutilised. You borrow money, keep that money unutilised but continue to pay interest thereon. What is the meaning of that? We pay interest and instalments, for that matter.

I found in a note given by the Budget section that the expenditure will also be higher as the Government is gradually moving towards market related rates of borrowing. You should be conscious of this fact. Also they say that the interest payment alone is expected to register an increase of over 6,000 crores of rupees in the 1993-94 Budget. This statement has been made by the Government itself and if this is the real position, then I do not know the manner in which the Budget is going to be utilised for development purposes and balanced, for that matter. The World Bank says that only by implementing the Narasimham Committee report a solution can be found. What does the Narasimham Committee report say about it? Cut down the priority sector advances starve the rural credit-hungry rural poor people and the agriculturists. They are poor and marginal farmers. They do not get the credit at the concessional rate of interest with the result they become victims of the rural money sharks. The Narasimham Committee report also warned that the nationalised banking sector should be squeezed and curtailed. The result has already started coming. The Canara Bank has started closing down its branches. The first target will be the rural branches. They will be closing them down. There will be closing down of branches in the industrial and urban areas thus paving the way for more foreign banks to come into the picture. Already, a scam has been reported in respect of the foreign banks. It has also been the experience that foreign banks take little interest in promoting the economic development of our country. Still the Government wants them to come into the field. The Narasimham Committee has recommended free entry of foreign banks who do not contribute even 15 per cent of their outlay and profit to the priority sector. The contribution of the Indian banks in this respect is 40 per cent. But still, more foreign banks are required to be there because the World Bank wants it Now the World Bank and the International Monetary Fund have been saying that the economic reforms that have to take place in our country are not taking place according to their prescriptions and they put a lot of pressure on the implementation of the Narasimham Committee recommendations. We know how the Narasimham Committee recommendations were made public last year. They were finalised in 90 days' time. Then we said this that what they did at that time was mainly at the dictates of the World Bank and the IMF. However strongly the Finance Minister and the State Ministers for Finance might be saying, "No, we are preparing our policy on our own and not at the dictates of the international institutions," the fact is that they have been doing what the World Bank has been asking them to do. What is the position of the recovery of bad debts? Big industrialists, big business houses have borrowed funds from the banks but they are not repaying it. Bad debts are to the tune of Rs. 25,000 crores. They have been termed as non-performing assets and we do not make any changes in the law for the recovery of these advances. Instead, Government think in terms of having the Assets and Reconstruction Fund which is also to be contributed by these banks and they will be empowered to take out these funds from the commercial banks at a heavy discount and recover them. Why cant we authorise the commercial banks with full powers to recover these bad debts in an effective way from the people who have taken this money? The borrowers and guarantors, have got enough resources. They simply swindled the common man's money from the commercial banks.

Now I talk about the balance-sheeet. We want that there should be a transparent balance-sheet.

We have been demanding that the names of the persons who have borrowed about 50 lakhs of rupees and more but who are not paying back should be published. What is the hestitation to come out straightforward? The reason is they do not want the names of the persons who support the ruling party and give money from their resources obtained from banks should be disclosed. They don't repay it to the banks but they utilise it for other purposes, including subsidising the political forces whom they support.

Again, the question comes about rural credit. A National Rural Bank of India has been conceived. has been talked about. Some draft has been prepared. Even now we don't find any complete shape being given to it so that the rural poor could be ensured of some institutional credit in a proper form, instead of being squeezed by the big men.

Another question comes. The pension scheme. Ten lakh financial sector employees have asked the Government to introduce a contributory pension as a third retirement benefit. Several thousand crores of rupees can be mobilised, which can be utilised for development purpose, instead of borrowing money from elsewhere. No decision has been taken. No final discussions are taking place. Not only the employees would be benefited, but at the same time resources could be mobilised and they could be utilised for other purposes by the Government itself instead of going for more and more borrowing. This Economic and Industrial Policy of the Government is anti-people, anti-national. This Government is carrying the country to a state of destitution, destitution of the people and mortgaging of our country. We cannot allow this Government to have more funds to pursue this game of their own. We don't support it. Government must change their attitude and reverse this Economic and Industrial Policy; otherwise, the people of this country will revolt against it.

I warn, I caution the Government that the time has come when a communal frenzy has been whipped up by certain political forces in our country whether they should get the honour to be in the Legislatures and Parliament also. You should change your thinking about them. I want to know whether you will be chasing those communal forces only and under the cover of this whether these bad Economic and Industrial Policies would be pursued against the people. Again, I confirm, I oppose this Bill and oppose this Bill from every angle. Government must go back and have a re-thinking about the Economic and Industrial Policy.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri Kamal Morarka.

DR. NAUNIHAL SINGH (Uttar Pradesh): Madam, I want to make one point. I wish to make a point with your permission.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Is it a point of order?

DR. NAUNIHAL SINGH: I wish to mention here that millions of dollars were placed at the disposal of the Government of India by the World Bank... *(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Is it a point of order?'.. *(Interruptions)*...

DR. NAUNIHAL SINGH: Those funds were not utilised. For the non-usage of those funds the Government has to pay a lot of money. That's all.

SHRI KAMAL MORARKA (Rajasthan): Thank you, Madam. A lot of points have been made by my colleagues and I was delighted to hear the hon. Member of the BJP criticising the Government hammer and tongs on the Economic Policy. Ever since the Government assumed office. Madam, we on this side have pointed out the fallacy of the Economic Policies which under the garb of some new Economic Policy they are trying to foist on the country. In their enthusiasm, in the beginning they took three measures. The moment they took office, they took these three measures. One was the devaluation of the rupee. Another was the dual exchange rate which is

[Shri Kamal Morarka]

being called partial convertibility. It is a wrong term. There is no convertibility. There is a dual exchange rate and import of gold. Madam, objectively speaking, import of gold has been successful. From the answer to a parliamentary question I find about ten to twelve tonnes of gold is coming to the country through the official channel which, I think, is a good sign and to that extent smuggling was curbed. The dual exchange rate was for a specific purpose that the essential imports of the country, namely, crude oil and fertilizers, could be covered at a lower exchange rate and the rest of the economy could balance its export and import. The devaluation of the rupee, the Government has told us, would lead to a boost in exports. After one-and-a-half years today this Government is about to present its third Budget in February 1993—let us take stock of what is happening. Yesterday the Finance Minister has told the House that in the first six months of this year the adverse trade balance was 2.7 billion dollars. I understand by the end of this financial year, the country would be running up a trade deficit of six billion dollars, the highest in the history of this country. Six billion dollars by any standard, is a very whopping trade deficit for a country like ours. How does the Government want to meet it? The Government says the balance of payments position is good, which means either loans or the non-resident deposits. Even the non-resident deposits, from an answer to a parliamentary question, I find that the outflow is more than the inflow right uptill September, 1992. It means you are trying to copy which you cannot afford. You are trying to copy Mr. Bush and Mrs. Thatcher. They have an adverse trade balance and they have tried to make it good by capital inflow. The Government has told us that after liberalisation about three billion dollars would come into the country every year by way of investments. The total money that has come is about Rs. 100 crores as per their own figures. Dr. I. G. Patel, one of the foremost economists of the country, former Governor of the Reserve Bank of India, former Secretary (Finance), has initially supported the restructuring or stabilisation programme. Even he has been constrained to say now that trying to meet trade deficit by capital inflows is a faulty proposition and the Government should not think, in the long run, unless your trade balances, that the country will come out of the economic morass. Now, according to the figures quoted by the Government themselves, the exports have gone up by 6.1 per cent; the imports have gone up by 52 per cent. I don't understand how on earth a country can function properly if imports are going up at the rate of 50 per cent per year and exports are going up at the rate of 6 per cent per year.

SHRI JAGESH DESAI: The trade deficit is double that of last year....

SHRI KAMAL MORARKA: Mr. Jagesh Desai, who is very knowledgeable in this matter, has very rightly pointed out that as compared to this point of time last year the trade deficit has doubled. Now nothing stops the Government from taking interim measures. In the midddle of the year they can certainly clamp down on imports. I don't think that they will go in for severe import compression. They go on pointing out what my colleague, Shri Yashwant Sinha, has done to save the country from bankruptcy, the severe import compression, as fit was a wrong that was done. They try to tell us that the imports are required to boost the exports. They try to tell us that imports are required to improve industrial production. The fact of the matter is, according to their own figures, that the import has increase to an unsustainable level; industrial production has gone down; export has made a meagre increase which it could have increased in any way. Six per cent increase is the annual average, whatever you may do or not. In these circumstances, the first measure which the Government must take—I am

sorry that the Government has done nothing on this front—is to bring about a modicum of balance between exports and imports. Please cut down imports. If import is taking place which is not going to export or industrial production, what kind of imports are there? We don't know. Elitist consumption goods and non-essential imports are on the defence side. The House is kept in the dark in the name of security. But there are a lot of defence imports which are taking place, which we don't know. Let there be a committee of Members. I don't mind if the defence matters are kept secret. Let them not be discussed on the floor of the House. But certainly the Public Accounts Committeee can look into it. The COPU can look into it. But most of these things are kept out of public view. With the result that the examples which you gave Korea, Taiwan, Singapore—apart from the fact that these countries are very small—do not apply to us. Even then the imports are export-related and industrial output-related. You don't even know what your imports are. Your imports are for consumption. With the result, after six months you find whatever you might have done, whatever goods might have come incidentally because of the policy, is all wasted. Madam, I come to only two or three points which are very fundamental. One is food. We always give the example of Soviet Union here. We have pointed out to you that it is not a question of ideology having collapsed in the Soviet Union. We do not share that view. We do not even share the view that the last word on the Soviet Union has been said. Do not go by current transition. But in the case of two things, the Soviet Union did make a mistake I am sorry to say that you are repeating that mistake. One is, the Soviet Union's agricultural output collapsed. They had to depend on America for wheat. You are making the same mistake. You are withdrawing fertiliser subsidy. Food production has not yet been affected. But in the eighties we had seen it. Mrs. Gandhi herself knew it and she corrected it immediately when she saw that by withdrawing fertilizer subsidy food output was getting affected. She did not want India to go back to the days when food had to be imported from America. When she took over as Prime Minister food was being imported and she had to suffer humiliation in America and had to devalue the rupee. At that time she said 'Never again as long as I am the Prime Minister will I allow this to happen.' She went in for a green revolution. It is all history. This Government is bent on reversing that. You want to go back to the days of food deficit. Already wheat is being imported. It is a big scandal already and everybody knows about it. Eevn if the food output stagnates, because the population is going up, we will be in trouble. So please do not do it. What are the figures? April to September 1992, the procurement has fallen by 14 per cent. It was 95.32 lakh tonnes. Now it is only 82.21 lakh tonnes. Last year 93.73 lakh tonnes was lifted by the PDS. This year it is 88.37 lakh tonnes. It has gone down. Food grain stock as on 1st October 1992 is only 103.91 lakh metric tonnes as compared to 157.3. It is 47.4 per cent lower. In one year we have eaten up our stocks by 47 per cent. This is the state. God forbid, if there is one draught, we will be wiped out. We are having good monsoons. Fortunately, good monsoons have been there for the last three years. Just to put the Government in trouble I do not wish something bad. I wish good monsoons remain with us for the next couple of years. But your food-grain position is such that you will not be able to withstand even one adversity. This position has not been there for the last 20 years. You are at a precarious low as compared to the last 20 years. The second basic thing is crude oil. per cent dual exchange rate is for the import of crude oil. I had asked a Parliamentary question which was answered on 25th November, 1992 What is the crude oil output? What

[Shri Kamal Mororka]

is the crude oil import? The production figures show:— 1989-90: 34.99 million metric tonnes. 1991: 33.00. 1991-92: 30.345. The target for crude oil for 1992-93 is 28.46. There is a 20 percent drop in the production of crude oil in three and a half years. This is a major sector of the economy which is floundering. I have not heard one statement from the Government or even one expression of concern from the Government. On the import of crude oil, Government's own figures in reply to my question show— In 1989-90 it was 19.49 million metric tonnes. In 1991 it was 20.49. In 1992 t is 23.99. Ths year the Government has approved 26.66 million metric tonnes. There is a 40 per cent increase in the import of crude oil in three years. I do not know what kind of Finance Minister he is! How can he sustain this economy if the crude oil import increases at this rate? After all, crude oil costs money in dollars. It is just unsustainable. They give us figures. Yesterday in the Question Hour hte Finance Minister said that the economy is steadily improving. All the newspapers said that today. What is the improvement? We will meet the fiscal deficit. At what cost? Without spending on development. No poor country, no developing country can develop without spending money. You are spending your elementary revenue in your revenue expenses. You want to maintain the fiscal deficit. It means a out in the expenditure for making new schools, colleges, hospitals, etc. You are mortgaging the tomorrow for today. Nothing will come out of it. I don't understand what kind of a planning is going to take place. Reducing the fiscal dificit is no and in itself. It is a means to achieve and end. The end is the development of the country. Even in today's appropriation Bill, most of the money involves only a change of head; from one head to the other. My friend, Mr. Shankar Dayal Singh, rightly pointed out, Rs. 10 crores were spent on Ministers' travelling, Rs. 3 crores on MPs, etc. If you want to create an atmosphere of austerity, we will have to begin it. We cannot say that austerity has to go to the people. Even the President elect Clinton, in a country like America, has been elected on the promise that he would increase the Government spendings on the creation of employment and infrastructure. We are still in the Bush-Reagan era which has been rejected even by the America people. We still believe that the trickle-down economics will work. We still believe that if we reduce the tax on the rich, if you reduce the tax on the corporate sector and if we allow the stock market to go on the rest of the country will develop. This has failed even in America. This has been debated there. Bush said, "Yes, it will work. I will persist with my policy." Clinton said, "It will not work." People have elected Clinton. Even the people of America know that it will not work. I do not know when we will come to know about it. According to me, it is high time they gave up this trickle-down ecenomics. The Government should immediately take up the spending programme. The new Budget is coming. I take this opportunity to tell the Government, in the new project, please have a large spending programme on the social sector. For that, the Budget deficit and the fiscal deficit can take a back-seat. You cannot put the fiscal deficit into shape and cut all the spendings on the capital account. It just won't work. The need of the hour in the developing countries is to create employment. All their programmes are geared to create unemployment. They first create employment and then they say that they have a security net, the National Renewal Fund. Madam, I give them a better proposal. Instead of the renewal fund, please spend that money on creating employment. Nobody wants your money to go home. People want to do a job and take their salary. In this entire economics a U-turn must be taken. We—when I say, 'we', most of the Left Parties, Janata Dal, and ourselves—have been crying hoarse

from the day you took office, "don't follow this policy." It is a dangerous proposition to say that for the last 40 years, the Indian policy has failed. It is a dangerous proposition because those countries which have done that have failed. In the Soviet Union, for example, their agriculture failed. The second mistake they made was they were dependent on the IMF and the proimses made by the IMF. President Gorbachev is on record as having said that the promises made to him in Washington were not fulfilled. The whole country is balkanised, is broken up. I don't understand this temporary thrill that we get by feeling as if the CPI and the CPM friends are uncomfortable. I am not concerned....

SHRI M. A. BABY (Kerala): We are not.

SHRI KAMAL MORARKA: They should not be. The point is, we must learn from history. We should not repeat the same mistake. If you go into an era of food shortages and if you go into an era of dependence on the imports, your country suffers. I do not know how much connection there is between the two; but you cannot escape from the developments of 6th December. According to me, it is a watershed in India's independent history. What has happened on 6th December is going to have effects for decades in future. And when this Government took office and tried to follow this line and when we told them that it was wrong, it took the support of the very parties, just to get the Budget pased, who made fun of the so-called Nehruvian model. They openly said "we support this Budget because it rejects the Nehruvian model." We say with all the emphasis at our command that the policies of the freedom struggle, whether political or economic or social, are the only policies which can stand us in good stead. And any deviation from these policies will only lead to disaster. What has happened on 6th December is only an eye-opener. The earlier you get out of this kind of thinking the better. As my friend, Mr. Ramdas Agarwal, said, —of course, he was poking fund at my Leftist friends—I will be very happy if one of the fall-outs of this tragic episode is that the Congress reserses these disastrous policies and consults the Left and other democratic socialists and brings the economy back on the rails as it was for 40 years. There is basically nothing wrong. Prof. Galbraith, who was an Ambassador to India, was one of the foremost economists in the world; certainly he was bigger than most of the economists who are among us today. He was in India and he said, 'Indian agriculture policy has succeeded. India should not be in a hurry to change the pricing policy or the withdrawal of subsidy. The International Monetary Fund may have different views. But I would advise the Indian pilicy-makers to listen to the International Monetary Fund pilitely but not take them seriously.' This is what Prof. Galbraith was advising you. He is more mature, more understanding of your country than what you. The Finance Ministry, from top to bottom, has got people whose mind set is World Bank, whose mind-set is International Monetary Fund. They cannot think beyond depending on America. The Soviet Union did that and see what they have come to. You tried to depend on some who believed that that was the right policy and look what you have come to. Please wake up. Please go back to the pre-August, 1991 situation. Please learn from Mrs. Gandhi. Please learn from the Congress Party. We will all support if you have nationalist economic policies based on our resources, based on employment generation, based on export, based on giving our economy a balance. We cannot afford the luxury of the West where accounting books take precedence over hard facts.

In Palamau, starvation deaths have taken place. Madam, I would like to bring to your attention that this is not a co-incidence. Twenty one years

[Shri Kamal Morarka]

ago when the country was in a similar position, when devaluation of the rupee took place, when we were cutting on capital expenditure, when we were depending on America, starvation deaths took place in Palamau, the same Palamau. It is not a coincidence. When elitist policies are taken, the lowest of the lowest are hit first. Palamau is one of the most backward areas in the country. Tribal people live there and their existence is hand-to-mouth. Every time you try to follow these policies, the people of Palamau will be hit first and as far as we are concerned, Palamau is India. Washington is not India. Bombay is not India. The Stock Exchange is not India. The people of Palamau, the people in the hinterland, are India. If we cannot tailor our policies for the wellbeing of our people, we have only ourselves to blame. But please do not believe all the sugar-coated policies of the West. They are not applicable to our country. Do not believe friends who believe that the Nehruvian model is out of date. Do not believe that Gandhiji is out of date, if at all we have to believe the Congress party. Even the Finance Minister spared no effort to point out the Soviet Union, even if they are trying to tell me that Adam Smith might have failed, Marx might have failed—I do not believe Marx had failed, but according to them—Gandhi has still not failed. Let Gandhiji be in our country. Somebody else has to come and remind us that our consumption must reduce, that we must live within our means. Why are we forgetting that Congress Party? Of course, this Congress Party can hardly claim the legacy to Gandhiji. That is a different matter. Most of the people who were there have left the Congress Party. Please put your house in order. In the name of God, please put your house in order. The country is at the cross-roads. After the 6th December, I am afraid most of what we are talking is becoming largely irrelevant unless you put the polity back in order and I am one of those, though I may be in a minority, who believe that there is a nexus between the kind of economic policies that you people have started and the kind of poilty that has developed now. It is not unconnected. There is a connection between the two and my friend, Shri Ramdas Agarwal has done a signal service to me by pointing out that. The economic policies are supported by them. Mr. Advani was the first man to say that this Prime Minister is the best Prime Minister that India has ever had. At least, you people should have accepted that certificate with a pinch of salt. I am sure you do not consider him greater than Jawaharlal Nehru. But all that you were enjoying is at the discomfiture of the socialist democrats. A time has come. Please introspect, please go back, please move three steps back and take a different route. In your natural route to prosperity, you have always got the support of the Left or the Socialist parties and you can count on them. But if you persist in your pro-Washington line, in subjugating this country to Western powers, I am sorry you will have nothing but the BJP on your hands.

Thank you.

PROF. SAURIN BHATTACHARYA: Madam, I was not really prepared for so closely following Mr. Kamal Morarka after the thundering applauses he received. So, what I say may be at a very low key. Since the Appropriation Bill is an occasion. I mean the discussion on the Appropriation Bill is an occasion when the entire gamut of the Government policy, particularly the economic policy, may be discussed, it is very well that from different angles the same thing may be done. But, before doing that, not just as a ritual, but from my heart of hearts, I feel it necessary to refer to the very changed situation in which this Appropriation Bill (No. 5) is being moved, the changed situation from when the Budget was passed. Our opposition,

that is, the opposition of the Left parties to the Budget presented by Dr. Manmohan Singh on behalf of the Central Government is well-known. We really oppose all the economic policies of the Government lock, stock and barrel. And we consider that they are designed to strengthen the stranglehold of the imperialist powers, of foreign multinationals, of foreign capital and the national monopoly capital on the economy of the country. That is all that liberaligation makes, as per the normal connotation of liberalisation accepted during the recent days globally. And our Finance Minister who has a global experience through the Bank-Fund institutions. has brought that concept into our economy but with disastrous results. As I was saying that Budget to which this additional expenditure is a supplement, that Budget was placed in particular circumstances whereas the Appropriation Bills are presented in altogether different circumstances. We heard the BJP spokesman. Mr. Agarwal, speaking how they supported initially the Government on its path to liberalisation and how they let them astray after 'Jai Sri Ram'. Even today we heard Mr. Pramod Mahajan clamouring for unfetterd right to have a 'mela' or something like that before the Ram Lalla mandir at Ayodhya, not content with the complete disaster that was enacted at Ayodhya on December 6. These are the people who are out to disrupt the country, to tear the country into pieces from limb to limb. They are pursuing that disastrous path. From that, the real import of what Mr. Advani said is now clear. It was really to put a hangman's noose round the neck of the Prime Minister by way of his liberal economy. This hangman's noose would have very well suited the BJP who in cynical disregard to all norms, all ethics, followed the line of power politics through the debauching of religion. We are not religious people. We have no love for religion. Our religion is a different sort of religion. But living in this country, we have never seen the name of Rama being dragged at the same pedestal with Mr. Advani and other leaders, and that campaign ultimately led to what happened on December 6. Now the entire country is topsy-turvey. Therefore, the economy cannot but be otherwise and in this situation, the Government has to deal with this situation in a firm manner by getting the support from all sides, barring the communal side. We all owe it to the country and to the Government. Let them not dither over this thing. The country is further disturbed from the side of Sangh Parivar, the BJP and their colleagues with communal intentions.

So far as the Appropriation Bill is concerned it is strange that there are no steps to reduce the price rise, at least to hold the price rise. It is strange that food subsidy is reduced and also the fertilizer subsidy. On the other hand, we are told that additional Rs. 500/- would be given to the farmers. If this is to be done, what was the harm in continuing the subsidy? What about the food subsi-

[Prof. Saurin Bhattacharya]

dy? What about subsidising the poor people below the poverty line? I don't know, Madam, what will happen. A committee of the World Bank is supposed to be preparing a document on higher education for implementation throughout the world. The World Bank is dictating the Government policy. The World Bank is dictating policies on so many issues, and if we are unable to confront them with our own determination, however much money we may advocate in this whimsical manner, and if we go on condoning corruption as in the case of Bofors or the magnitude of the problem as in the bank scam, we cannot achieve anything. What the JPCis doing is *post mortem*. It cannot prevent it. Preventive action has to be taken by the Government. But the Government has not decided what really it should do.

In this background, we are considering this Appropriation Bill. Therefore, in totality, action has to be taken by the Government to tackle the situation effectively and in such a manner that all sections of the House, barring the communalists, can support them. Thank you very much.

श्री भूपेन्द्र सिंह मान (नाम-निर्देशित) : धन्यवाद, मैडम । मैडम, एप्रोप्रिएशन बिल में 2,624 करोड़ रुपया सरकार ने मांगा है कि इतना निकालने की उसे इजाजत दी जाए । इस राशि को इंसाफ के तौर पर सभी सेक्शन, सोसायटीज में और देश के सभी नागरिकों में अच्छी तरह से बांटना इस सरकार का फर्ज होता है, लेकिन पिछले इतिहास को देखते हुए अगर मैं आपसे कहूं तो मेरा ख्याल है अच्छा होगा आगे का सोचने के लिए भी ।

मैडम, हमारे देश में कुल आबादी का 80 प्रतिशत किसान है । किसान ने जो चीजें बाजार से खरीदनी है और जो चीजें बेचनी हैं, उनकी एक पैरिटि होनी चाहिए, जो आज तक नहीं हुई । मिसाल के तौर पर सन् 1967–68 का प्राइस इण्डेक्स 100 था और इस वक्त नवंबर, 1992 में उसके मुकाबले यह 716.71 हो गया है । इसका मतलब यह है कि किसानों के बेचने वाली चीजों के भाव भी उतने ही देना चाहिए थे, लेकिन उस हिसाब से उसकी फसल के भाव नहीं बढ़े । उस वक्त किसान के गेहूं का भाव, मिसाल के तौर पर यदि एक फसल की बात कर लें तो उसमें सभी फसलें आ जाती हैं, तो उस वक्त किसान, जो गेहूं पैदा करता है, उसका भाव 75/– रुपए प्रति क्विंटल था और आज उसे 280/- रुपए दिया गया है । असल में पैरिटि के हिसाब से यह 537/- रुपए होना चाहिए था । प्राइस इण्डेक्स के हिसाब से ऐसा होना चाहिए था कि यह प्राइस इंडेक्स बढ़ा है 716.17 यानि लगभग सात गुना, अब 75/- रुपए का सात गुना कर लीजिए तो देखिए कितना होता है । वही मैंने किया 537/- रुपए होता है । इस हिसाब से यदि देखें तो सारे देश में जो इस साल गेहूं 567.65 लाख टन पैदा हुआ है, उसका किसान को मिलना चाहिए 30,404.8 करोड़ रुपया और जो उसको दिया गया वह है 14,566.6 करोड़ रुपया । इसका मतलब हुआ कि 15,838.2 करोड़ रुपया किसान का रोक लिया गया, उसकी जेब में नहीं जाने दिया गया । उस रुपए को रोककर, किसान की मेहनत का दाम कम देकर, जो उसने मेहनत की है यह इक्युटेबल डिस्ट्रिब्यूशन आफ वेल्थ नहीं रहा । अब जब सरकार इतनी राशि बजट से निकालकर लोगों पर डिस्ट्रिब्यूट करना चाहती है, लोगों को काम करने के लिए देना चाहती है और अगर यह डिस्ट्रिब्यूशन उसी ढंग से होता है, जिस ढंग से पहले होता रहा है तो यह देश के लोगों के

और खासतौर पर किसान वर्ग के हित में नहीं होगा । जो किसान वर्ग के हित में नहीं होगा तो वह देश के हित में नहीं होगा क्योंकि किसान वर्ग देश की 80 प्रतिशत आबादी है ।

मैडम, यह जो मैंने एक गेहूं की मिसाल दी है तो इसी तरह सारी 22 फसलों का देश मिनिमम सपोर्ट प्राइस नियत करता है और सभी ऐसी फसलों में किसान का हक, उसकी मेहनत का दाम उसको देने में रोक लगाई जाती है । कितने ही करोड़ रुपए किसान के पास नहीं जाने दिए जाते, उसके हक को रोका जाता है और इसकी बजाय बाहर से गेहूं मंगवाकर देश का इतना बढ़ा धन, इतनी मेहनत से कमाया हुआ धन बर्बाद किया जाता है, करोड़ों रुपयों में ही नहीं बल्कि यह डालरों और फॉरेन-एक्सचेंज में बर्बाद किया जाता है । अगर यह धन, जो किसान पैदा करता है, उसके पास रहने दिया जाए तो देश का प्रोडक्शन बढ़ सकता है, देश की उपज बढ़ सकती है और उपज बढ़ने से खुद-ब-खुद, जैसे कि सीधी सी बात है कि जब उपज बढ़ती है, मंडी में उपज ज्यादा आती है, उसके दाम नीचे आते हैं । मण्डी में हम माल बढ़ने नहीं देते, पैदावार किसानों को करने नहीं देते और बाहर से अनाज मंगवाकर यहां डिस्ट्रिब्यूट करके उसका इंटरेस्ट, उसकी मेहनत काटने की बात की जाती है । यह इंसाफ नहीं है, यह देश के हित में इंसाफ नहीं है । जो विधान में इंसाफ कहा गया है कि इंसाफ होना चाहिए इकोनोमिक, सोशल और पोलिटिकल, तो मैं इसमें इकोनोमिक, आर्थिक इंसाफ के बारे में कहता हूं कि जितनी देर तक सरकार आर्थिक इंसाफ देश के सबसे बड़े वर्ग को देने की बात नहीं करेगी और उस इंसाफ को काटकर, रोककर दूसरे वर्गों को देने की बात करेगी, यहां इस देश का प्रोडक्शन बढ़ नहीं सकता और यह प्रोडक्शन न बढ़ने की वजह से, मैं यह कहता हूं कि हमारा देश वाइबल देश नहीं हो सकता । जैसे जिस घर की पैदावार कम होती है और उसके खर्चे ज्यादा होते हैं वह घर वाइबल नहीं होता, ऐसे ही हमारा देश वाइबल देश आज तक इसलिए नहीं बना है क्योंकि हम पैदा उतना नहीं कर सके हैं, जितनी कि हमें जरूरत है और जितना हम खाते हैं । जितनी देर तक हम जो पैदा करता है, उसको उसकी मेहनत का उचित प्रोत्साहन नहीं देंगे, उसको इनकरेज नहीं करेंगे, उतनी देर तक यह प्रोडक्शन बढ़ नहीं सकती और मैं समझता हूं कि यह देश के हित में है कि जो काम करने वाले लोग हैं, उनको उत्साहित किया जाए । मैडम, किसान को उसकी फसल का भाव देने में उसकी मेहनत का दाम न दिया जाना, यह सबसे बड़ा उसके साथ धक्का है और अगर देखें तो 1967–68 से जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स है और अरबन नान मैन्युअल वर्कर्स है एग्रीकल्चरल वर्कर्स हैं, इनमें पैरिटी का हिसाब लगायें तो पता चलता है कि उस वक्त अगर 100 रुपए मेहनत थी तो आज इंडोस्ट्रियल वर्कर की 625 रुपए है, नान मैन्युअल अरबन वर्कर की 610 रुपए हैं और एग्रीकल्चरल वर्कर, जो 8 घंटे काम नहीं करता–8 घंटे काम करने वाले लोगों में भी शायद कुछ कम घंटे काम करते हों और दाम 8 घंटे का लेते हों, उसके बजाए 24 घंटे मेहनत से, ईमानदारी से काम करने वाला किसान, जो गांव में रहता है, उसको 460 रुपए की बात आती है । तो यह जो पैरिटी नहीं दी जा रही, यह देश के हित में नहीं है और इसलिए मैं कहता हूं कि जो भी इंसाफ के तौर पर, इंसाफ के तराजू आधार पर आर्थिकता बांटी जाए, वह ठीक होती है । विधान की परिभाषा को ठीक करते हुए हमें जो आर्थिक इंसाफ है उसको देश के सभी हिस्सों में इस ढंग से बांटना चाहिए कि सभी को उसका इक्वीटेबल डिस्ट्रिब्यूशन हो और सभी के हिस्से में जो आर्थिकता है, वह एक जैसी पहुंचे ।

मैडम, खुलापन जो सरकार कहती है, खुलेपन के लिए तो किसान को बाहर चीजें ले जाने की इजाजत नहीं है, जो वह पैदा करता है और बाहर से चीजें वह उस भेजी हुई राशि से मंगवाने की उसको इजाजत नहीं है, जब कि खुलेपन की परिभाषा में यह सीधा है कि हरेक को खुला होना,

[श्री भूपेन्द्र सिंह मान]

चाहिए कि अगर वह जो पैदा करता है उसे उसको बाहर भेजना है, तो वह उसे भेज सके । इसी वजह से किसान के साथ इस साल कपास में, पिछले साल कपास का दाम 1500 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास था और इस वर्ष उसी कपास का दाम 900 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास हो गया है और यह इस हिसाब से भी कि फर्टिलाइजर और दूसरी चीजों के भाव भी, जो पैरिटी प्राइस है, उसका भाव इतना बढ़ गया है, लेकिन फिर भी उसकी कपास का दाम पिछले साल के मुकाबले बहुत कम हो गया है ।

तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि यह जो बिल है, इस बिल में ठीक ढंग से डिस्ट्रिब्यूशन होना चाहिए, यह पैसा ठीक ढंग से बांटा जाना चाहिए और मैं समझता हूं कि यह आज तक ठीक ढंग से नहीं बांटा गया और इसमें से भी ठीक ढंग से नहीं बांटा जाएगा और इसीलिए मैं इसका विरोध करता हूं ।

DR. YELAMANCHILI SIVAJI (Andhra Pradesh): Madam, one of the main items of the Supplementary Budget is that Rs. 268 crore have been earmarked for the technical credit to foreign countries. Out of this, an amount of Rs. 258 crore is meant for Russian Republics and the rest of the Rs. 10 crore for Uzbekstan. As per the Protocol Agreement between Russian Republic and India on 22nd February 1992, banking arrangement was made between the two. It was reviewed during May and a Memorandum of Understanding was signed by the Commerce Secretary of the Government of India and his counterpart in Moscow. As per the Memorandum of Understanding, "the letters of credit for exports from India will be issued by the Reserve Bank of India and its counterpart in Moscow." It is also added in the Memorandum of Understanding in article 8 that all payments of commerical and non-commercial nature between the USSR and India will be effected in Indian rupee. So far, in the last budget, we had earmarked about Rs. 850 crore, and not satisfied with that we are again advancing Rs. 268 crore. The credit between the erstwhile USSR and India is in terms of rupee payment and it has become almost a millstone around the neck of our country, Since 1978 there is a disproportionate parity between the rate fixed for rouble and rupee and it is calculated that we owe an amount of Rs. 38,000 crore to Russia. As per the protocol rate, each rouble costs Rs. 38, but in the international market a dollar costs 500 roubles and the rouble is heading to hit the 1,000 rouble mark per dollar by the coming March. If that calculation is taken into account, the Rs. 38,000 crore Russian debt will come down to the tune of just Rs. 100 crores or much less than that. As per the original protocol of 1978 between the USSR and India, all the items traded between India and the USSR are to be paid for only in rupees, whether they are billed in roubles or dollars or rupees or whatever it is.

Between 1970-71 and 1981-82, the balance of payments position was comfortable for India and we were in possession of Rs. 1,235 crores plus. In the last three years, the trade advantage to India was to the tune of Rs. 7,000-odd crores. Yet, we are advancing money. As per the protocol, Moscow was supposed to export to India about four million metric tonnes of crude, but so far only 60,000 metric tonnes were exported to us. In addition to that, one million metric tonnes of diesel and kerosene also were supposed to be imported from Moscow, but nothing has come down from Moscow, and thereby our exports are affected. So, if Moscow is negotiating with the International Monetary Fund for a rouble-dollar exchange rate, the Government of India should take advantage of it and see that the rupee-rouble rate is fixed, not disproportionately but according to the real value of the rouble.

Our agro products are all the more being affected largely for want of exports to the erstwhile USSR. The socalled Soyuz Prodo Imports that signed the protocol and the orders for imports from India, that company has disappeared and, in its place, some other joint sector company has cropped up. And the USSR has almost disappeared. The Indian Oil Corporation has to shell down 60 million dollars to import oil outside the protocol. So, on the one hand we are advancing technical credit—which is almost a subsidy to Moscow—and, on the other, we are not getting any goods from the USSR. So it is a matter to be seriously considered by the Government.

It was reported in a section of the press, and it was also stated in Parliament on 24th April in an answer, that a huge amount has been smuggled through this route. Rupees are paid and from Moscow some payment is done in dollars. The Income Tax Department had conducted a raid and found something like Rs. 9 crores as unaccounted money in one of the banks in Delhi. So, the Government of India, more so the Ministry of Finance; should see that this racket is unearthed and all such malpractices are curbed.

In the current budget, 285 million dollars are earmarked as technical credit to Moscow, but it will not suffice. I, therefore, suggest that the rupee-rouble rate be refixed according to the real value existing now.

Another aspect I would like to touch is that it is also mentioned in the supplementary budget that an additional amount of Rs. 500 crores as subsidy is to be advanced to the fertilizer industry. But, Madam, it is a fact that in the fertilizer industry the subsidy is intended only to maintain the inefficiency of the fertilizer industry as well as the corruption in the Government of India. One of the fertilizer units that was started in the East Gadavari district of Andhra Pradesh was started with an estimated cost of Rs. 500 crores, but the estimate later on went up to Rs. 1,200 crores. The same fertilizer unit was suposed to produce both ammonia and urea from naphtha but it was converted into gas—based. Once it is converted into a gas-based unit, its cost of production is supposed to come down. But, on the contrary, from Rs. 500 crores, it went up to Rs. 1,200 crores within six years. One of the Chairmen resigned and went back, smelling some malpractice and fraud in the fertilizer industry there. Thereby on Rs. 1,200 crores minus Rs. 500 crores, that is, Rs. 700 crores, every year about 20 per cent is paid as the interest component, and another 20 per cent is calculated as depreciation, and the entire amount is charged towards subsidy.

I, therefore, suggest that the indigenous fertilizer industry be exposed to global competition. Let them compete. There is no point in compelling our farmers to pay four times more than what their counterparts in other countries are paying. If our indigenous industry cannot complete in the world market and charge that price, it does not have any business to exist. The Government of India is whitewashing the entire affair, stating that the subsidy is meant for the farmers ,but in practice the entire subsidy is being swallowed by the industry acting hand-in- glove with Government officials.

Thank you.

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल (उत्तर प्रदेश): मैडम, हम बोलना चाहते हैं।

شری محمد افضل عرف م۔ افضل: میڈم ہم بولنا چاہتے ہیں۔

+[ ]Transliteration in Arabic Script.

उपसभापति : आपकी पार्टी का तो टाइम खत्म हो गया।

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ भीम अफजल : हमने लिख कर दिया था।

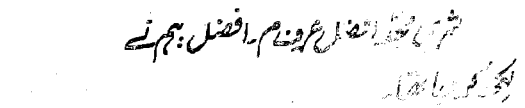

उपसभापति: चिट्ठी तो मुझे कोई मिली नहीं।

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ भीम अफजल : मैडम, दो मिनट का टाइम हमें दे दीजिए।

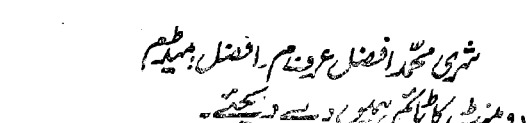

उपसभापति : ठीक है आप दो मिनट बोलिए। मैं आपका समय लिख रही हूं। एक बजकर 22 मिनट पर बोल रहे हैं आप।

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ भीम अफजल : मैडम, जो बिल आया है, मैं समझता हूं कि हमारी सरकार की जो इकनोमिक पॉलिसी है उसकी हम आज निंदा कर रहे हैं और हमेशा उसकी निंदा करते रहे हैं। तो खराब पालिसी का हमेशा खराब ही नतीजा निकलता है ये नतीजा भी खराब है। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा बल्कि मुख्तसर अलफाज में सिर्फ यह बात कहूंगा कि इकनोमिक पॉलिसी जो है, मुल्क की दूसरी चीजें भी उसके साथ जुड़ी हुई हैं और जैसा हमारे कमल मोरारका साहब ने बहुत तफसील से उसके ऊपर बहस की है, मैं समझता हूं मेरे जजबात और ख्यालात सब वैसे ही हैं। यहां इन्होंने पब्लिक वर्क्स के हैड में 9 करोड़ 97 लाख रुपया दिया है। मैं जानना चाहता हूं, इस वक्त यह बहुत ही अहम मसला है और सरकार ने ऐलान किया है कि वह मंदिर और मस्जिद बनाएगी। तो क्या अयोध्या के अंदर मंदिर और मस्जिद बनाने के लिए पैसा होम मिनिस्ट्री की ओर से दिया जाएगा या पब्लिक वर्क्स के हैड से निकालेंगे और अगर निकालेंगे तो उसका क्या तरीका होगा ? क्या कोई ऐसा प्रॉविजन किया गया है ? या आप दोनों समुदायों के लोगों से अपील करके उनसे चंदा लेकर मंदिर-मस्जिद बनवाने का इरादा रखते हैं।

मैडम, मैं यह कहना चाहता हूं कि "राष्ट्रीय सहारा" एक डेली अखबार है। आज के इस अखबार में फ्रंट पेज पर यह लिखा हुआ है कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के विवाद को हल करने के लिए सरकार मथुरा की तर्ज पर कोई फार्मूला पेश कर रही है। हमारे कल्पनाथ राय जी यहां बैठे हुए हैं। उनके बारे में कहा गया है कि शायद उन्होंने इस फार्मूले को पेश करने की कोई योजना बनाई है और प्राइम मिनिस्टर को दी है। मैडम, यह बहुत सीरियस मैटर है। मैडम, मथुरा के अंदर जिस तरह से हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर उस विवाद को तय किया था, उसके नतीजे में मथुरा में हमेशा अमन और शांति रही और वहां झगड़ा कभी वहां के लोकल लोगों की तरफ से नहीं हुआ।

जो उन्होंने मुहायदा तय किया था मेरे पास उसकी कॉपी मौजूद है और अगर जरूरत हो तो मैं सरकार को दे सकता हूं। क्या वैसा ही समझौता सरकार अयोध्या में करने जा रही है ? मैं

†[ ]Transliteration in Arabic Script.

सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं और होम मिनिस्टर से बहुत गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि इस मसले को लेकर हिन्दुस्तान में सिर्फ दो पार्टियों को ये समझ लिया गया है कि जैसे वे ही हिन्दुस्तान के तमाम मुसलमानों की वकालत करती हैं। उसमें एक बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी है और एक बाबरी मस्जिद राबता कमेटी है। बाबरी मस्जिद राबता कमेटी शहाबुद्दीन साहब की सदारत में चलती है और एक्शन कमेटी सलाउद्दीन उवसी साहब की सदारत में चलती है। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं कि ये हिन्दुस्तानी मसलमानों की अकेली तर्जुमान जमातें नहीं है। मेरी राय है कि अगर इस किस्म का कोई प्रपोजल कल्पनाथ जी ला रहे हैं तो मैं समझता हूं कि यह बहुत ही अच्छा काम है। मैं उनको मुबारकबाद दूंगा अगर वे इस मसले को हल करने से मथुरा की तरह का कोई फार्मूला लेकर आए हैं और अगर दोनों हिन्दु और मुसलमान समुदाय उसको मान लें तो यह बड़ी अच्छी बात है लेकिन मैं यह कहूंगा सरकार से और इस सिलसिले में मैं वजीरे आजम से भी कह चुका हूं, बहुत तफसील से गुफ्तगू की मैंने और बताया उनको कि मुस्लिम मेंबराने पार्लियामेंट भी इस मुल्क के मुख्तलिफ जमातों के अंदर है हिन्दुस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदगी इस सबसे बड़े प्लेटफार्म पर कर हैं, पार्लियामेंट के प्लेटफार्म पर करते हैं। लिहाजा उन मुस्लिम मैंबराने पार्लियामेंट से मशविरा तो करते हैं, लेकिन मेरी राय यह है कि आप बाकायदा उसको मान्यता दीजिए। जिस तरह से आप ऐक्शन कमेटी को बुलाकर गुफ्तगू करते हैं, जिस तरह आप कोआर्डिनेट कमेटी को बुलाकर गुफ्तगू करते हैं, इसी तरह आप मुस्लिम मैंबराने पार्लियामेंट को जिस पार्टी से भी वह ताल्लुक रखते हैं, उनसे भी यह पूछिए कि उनका नजरिया क्या है और उनको उतना ही वजन दीजिए जितना वजन आप ऐक्शन कमेटी या राफ्ता कमेटी को देते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे मुस्लिम नुमाया हैं जिनकी बात का वजन सिर्फ देश में ही नहीं, देश के बाहर भी सुना जाता है। मिसाल के तौर पर मौलाना अली मियां का नाम मैं लूंगा या और हमारे मुजाहिदुल इस्लाम कासिम साहब एक आदिम हैं, वह दोनों में से किसी कमेटी में नहीं हैं। उन उलामा से भी आपको राय लेनी चाहिए...

उपसभापति : अफजल साहब यह चिटठी लिखकर भेज दीजिए न आप।

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ भीम अफजल : मैडम मैं खत्म कर रहा हूं, इस प्लेटफार्म से जाएगा तो सरकार ज्यादा गौर से सुनेगी और मैं समझता हूं देश के हित में यह बात कह रहा हूं। ...(**व्यवधान**)

श्री संघ प्रिय गौतम : इस देश के बौद्ध, सिख, ईसाई मेंबरों से भी पूछा जाए क्योंकि यह देश केवल हिन्दू और मुसलमानों का ही नहीं है, यहां ईसाई भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं। यहां मंदिर भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं, जैन मंदिर भी हैं। उनसे भी पुछा जाए। सभी धर्मवलंबियों से पुछा जाए। ...(**व्यवधान**)

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ भीम अफजल : मैडम जो बात उन्होंने कही, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि सबसे पहले अपनी पार्टी में इसको लागू करें। ...(**व्यवधान**) जो विवाद इन्होंने विश्व

[श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल]

हिन्दू परिषद को दिया था उसको खत्म करें। . . . (व्यवधान)

श्री संघ प्रिय गौतम : मैं स्वयं बौद्ध हूं और बी०जे०पी० में हूं, इसमें ज्यादा क्या लाग् होगा ?

उपसभापति : अफजल साहब, अब भाषण खत्म करिए. . . . (व्यवधान)

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल : मैडम, मैं खत्म कर रहा हूं। आप हाउस एक्सपर्ट के मेंबर नहीं हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह विवाद एक ऐसे मोड़ पर आ गया है कि हम इस समय जो आग लगी हुई है उसको मजीद हवा देने की कोशिश न करें। कमल मोरारका जी ने बहुत वाजेह इशारा किया है. . . अगर यह मसला तय करने के लिए सरकार जा रही है तो इन बातों को जो मैंने कही है उन पर गौर करें।

उपसभापति : बस हो गया, आप बैठिए। आप प्रधान मंत्री जी को चिट्ठी लिख दीजिए।

श्री राम नरेशयादव : (उत्तर प्रदेश) महोदया, महोदया, . . .

صرف یہ بات کہوں گا کہ اکانومک پالیسی جو ہے ملک کی دوسری چیزیں بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور جیسا ہمارے کمال مرار کا صاحب نے بہت تفصیل سے اس کے اوپر بحث کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں میرے جذبات اور خیالات ویسے ہی ہیں۔ یہاں انہوں نے پبلک ورکس کے ہیڈ میں ۹ کروڑ ۹۷ لاکھ روپیہ دیا ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں اس وقت یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور سرکار نے اعلان کیا ہے کہ وہ مندر اور مسجد بنائے گی تو کیا ایودھیا کے اندر مندر اور مسجد بنانے کیلئے پیسہ ہوم منسٹری کی طرف سے دیا جائے گا۔ یا پبلک ورکس کے ہیڈ سے نکالیں گے اور اگر نکالیں گے تو اس کا کیا طریقہ ہوگا کیا کوئی ایسا پروویزن کیا گیا ہے یا آپ دونوں سیکولر والوں کے لوگوں سے اپیل کر کے ان سے چندا لے کر مندر مسجد بنوانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔

میڈم میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ "راشٹریہ سہارا" ایک ڈیلی اخبار ہے۔ آج کے اس اخبار میں فرنٹ پیج پر یہ لکھا ہوا ہے کہ بابری مسجد رام جنم بھومی کے وواد کو حل کرنے کے لئے سرکار مقدمہ کی طرز پر کوئی فارمولہ پیش کر رہی ہے۔ ہمارے کلپ ناتھ رائے جی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ شاید انہوں نے اس فارمولہ کو پیش کرنے کی کوئی یوجنا بنائی ہے

شری محمد افضل عرف م۔ افضل (اتر پردیش) میڈم جو بل آیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سرکار کی جو اکانومک پالیسی ہے اس کی آج ہم نندا کر رہے ہیں اور ہمیشہ اسکی نندا کرتے رہے ہیں تو خراب پالیسی کا ہمیشہ خراب ہی نتیجہ نکلتا ہے یہ نتیجہ بھی خراب ہے۔ میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا بلکہ مختصر الفاظ میں

[ ]Transliteration in Arabic Script.

اچھا کام ہے۔ میں ان کو مبارکباد دوں گا۔ اگر وہ اس مسئلہ کو حل کرنے میں متھرا کی طرح کا کوئی فارمولہ لے کر آتے ہیں اور اگر دونوں ہندو مسلمان سمپردائے اس کو مان لیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے لیکن میں یہ کہوں گا سرکار سے اور اس سلسلہ میں وزیر اعظم سے بھی کہہ چکا ہوں بہت تفصیل سے گفتگو کی میں نے اور بتایا ان کو کہ مسلم ممبران پارلیمنٹ بھی اس ملک کے مختلف جماعتوں کے اندر ہیں۔ وہ بھی ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندگی اس سب سے بڑے پلیٹ فارم پر کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم پر کرتے ہیں۔ لہٰذا ان مسلم ممبران پارلیمنٹ سے مشورہ تو کرتے ہیں۔ لیکن میری رائے یہ ہے کہ آپ باقاعدہ اس کو مانیتا دی جیسے جس طرح سے آپ الیکشن کمیٹی کو بلا کر گفتگو کرتے ہیں جس طرح آپ کو آرڈی نیشن کمیٹی کو بلا کر گفتگو کرتے ہیں اسی طرح آپ ممبران پارلیمنٹ کو جس پارٹی سے بھی وہ تعلق رکھتے ہیں۔ ان سے بھی یہ پوچھئے کہ ان کا نظریہ کیا ہے اور ان کو اتنا ہی وزن دیجئے جتنا وزن آپ الیکشن کمیٹی یا رابطہ کمیٹی کو دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے مسلم علماء ہیں۔ جن کی بات کا وزن صرف دیش میں ہی نہیں۔ دیش کے باہر بھی سنا جاتا ہے مثال کے طور پر مولانا علی میاں کا نام میں لوں گا یا

ہے اور پرائم منسٹر کو دی ہے۔

میڈم۔ یہ بہت سیریس میٹر ہے۔ میڈم متھرا کے اندر جس طرح سے ہندوؤں اور مسلمانوں نے مل کر اس وواد کو طے کیا تھا۔ اس کے نتیجہ میں متھرا میں ہمیشہ امن اور شانتی رہی اور وہاں جو جھگڑا کبھی وہاں کے لوکل لوگوں کی طرف سے نہیں ہوا۔

جو انہوں سے معاہدہ کبھی طے کیا تھا۔

میرے پاس اس کی کاپی موجود ہے اور اگر ضرورت ہو تو میں سرکار کو دے سکتا ہوں۔ کیا ویسا ہی سمجھوتا سرکار ایودھیا میں کرنے جا رہی ہے۔ میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں اور ہوم منسٹر سے بہت گمبھیرتا کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اس مسئلہ کو لے کر ہندوستان میں صرف دو پارٹیوں کو یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ جیسے وہ ہی ہندوستان کے تمام مسلمانوں کی وکالت کرتی ہے۔ اس میں ایک بابری مسجد ایکشن کمیٹی ہے اور ایک بابری مسجد رابطہ کمیٹی ہے۔ بابری مسجد رابطہ کمیٹی شہاب الدین صاحب کی صدارت میں چلتی ہے۔ اور ایکشن کمیٹی صلاح الدین اویسی صاحب کی صدارت میں چلتی ہے۔ میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہندوستانی مسلمانوں کی اکیلی ترجمان جماعتیں نہیں ہیں۔ میری رائے ہے کہ اگر کہ اس قسم کا کوئی پرپوزل کلینا تھ جی لا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی

†[ ]Transliteration in Arabic Script.

ہوں اور بی جے۔پی۔ میں ہوں۔ اس سے زیادہ کیا لاگو ہوگا

اپ سبھاپتی: افضل صاحب۔ اب اپنا بھاشن ختم کریئے۔۔۔۔ "مداخلت"۔۔۔۔

شری محمد افضل عرف م۔ افضل: میڈم۔ میں ختم کر رہا ہوں آپ آر۔ایس۔ایس کے ممبر نہیں ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دواد ایک ایسے موڑ پر آگیا ہے کہ ہم اس سمے جو آگ لگی ہوئی ہے اس کو مزید ہوا دینے کی کوشش نہ کریں۔ کمل مرارکا جی نے بہت واضح اشارہ کیا ہے۔۔۔ اگر یہ مسئلہ طے کرنے کے لئے سرکار جا رہی ہے تو ان باتوں کا جو میں نے کہی ہیں ان پر غور کریں۔

उपसभापति : मंत्री जी को बुलाया है।....

Whether he is the Minister in waiting or not, the Minister present here is waiting.

SHRI KAMAL MORARKA: Madam, BJP Members are always interested in their personalities.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): Madam, I don't understand why they are wasting the time of the House.

श्री राम नरेश यादव: महोदया, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं....

اور ہمارے مجاہد الاسلام قاسمی صاحب ایک آدمی ہیں وہ دونوں میں سے کسی کمیٹی میں نہیں ہیں۔ ان علماء سے بھی آپ کو رائے لینی چاہیئے۔۔۔

اپ سبھاپتی: افضل صاحب یہ چٹھی لکھ کر بھیج دیجئے نا آپ۔

شری محمد افضل عرف م۔ افضل: میڈم میں ختم کر رہا ہوں۔ اس پلیٹ فارم سے جائے گا تو سرکار زیادہ غور سے سنے گی اور میں سمجھتا ہوں دیش کے ہت میں یہ بات کر رہا ہوں میں۔۔۔۔ "مداخلت"۔۔۔

سنگھ پریہ گوتم: اس دیش کے بودھ سکھ عیسائی ممبروں سے بھی پوچھا جائے۔ کیونکہ یہ دیش کیول ہندو اور مسلمانوں کا نہیں ہے یہاں عیسائی بھی رہتے ہیں۔ بودھ بھی رہتے ہیں۔ سکھ بھی رہتے ہیں۔ یہاں مندر بھی ہیں۔ گوردوارے بھی ہیں۔ جین مندر بھی ہیں۔ ان سے بھی پوچھا جائے۔۔۔ "مداخلت"۔۔۔

شری محمد افضل عرف م۔ افضل: میڈم جو بات انہوں نے کہی میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنی پارٹی میں اس کو لاگو کریں۔۔۔ "مداخلت"۔۔۔ جو وواد انہوں نے وشو ہندو پریشد کو دیا تھا اس کو ختم کریں۔۔۔۔ "مداخلت"۔۔۔۔

شری سنگھ پریہ گوتم: میں سوئم بودھ

†[ ]Transliteration in Arabic Script.

उपसभापति: सवाल पूछ रहे हैं, इसी पर....पूछ लीजिए।

श्री राम नरेश यादव: महोदया, यह ऐप्रोप्रियेशन बिल जो आया, है इसमें 500 करोड़ रुपए की सबसिडी देने की बात है। बजट में 5000 करोड़ रुपया रखा गया था, इस तरह से 5500 करोड़ रुपया हो गया है। लेकिन जो बढ़ती हुई देश की जनसंख्या है जो बेकारी है, उसको ध्यान में रखते हुए कृषि क्षेत्र को हमारी सरकार प्राथमिकता देती है। पार्टी की नीति है उसके आधार पर सरकार चलती रही है। लेकिन इस बात को ध्यान में देखते हुए कि सब को खाने की बौछार करनी है, विदेशी मुद्रा अर्जित करनी है, और इस बढ़े हुए फर्टिलाइजर की वजह हमारा कृषि क्षेत्र बहुत ही भविष्य में प्रभावित होने जा रहा है क्योंकि किसान परेशान हो रहा है और उसको खाने के लिए व्यवस्था करनी है। कृषि पर आधारित व्यवस्था करनी है इस बात को ध्यान में रखते हुए मंत्री महोदय से एक उत्तर चाहूंगा। देश की इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए किसान ही नहीं किसान तो देश की रीढ़ है और देश की रीढ़ को ध्यान में रखते हुए और बढ़े हुए खाद के दाम को ध्यान में रखते हुए मंत्री जी आपने जो 500 करोड़ रुपये की सबसिडी रखी है यह तो ठीक है लेकिन उसके आगे भी क्या खाद के दाम को कम करने पर विचार करेंगे ताकि देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बाहर से आयात न करना पड़े और विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकें? यह मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं।

SHRI SHANTARAM POTDUKHE: Madam Deputy Chairman, I am thankful to the House and to all the hon. Members who have participated in the discussion of the Bill for appropriation.

Madam, I come before this hon. House with the second batch of Supplementary Demands consisting of 21 items, amounting to a little over Rs. 2,600 crores. Of this, around Rs. Rs. 1,390 crores are matched by savings and higher receipts. The net cash outgo will, therefore, be around Rs. 1,233 crores. We hope that with buoyant revenues this may not ultimately affect the fiscal deficit.

Madam, among others, additional provisions are being sought for fertilizer subsidy taking into account the various adjustments that have taken place in recent months. Additional funds are also being sought for improving the network of rural godowns, distribution through mobile vans and further measures to strengthen the public distribuion system in the most needy areas. In the light of the Supreme Court's direction, one lakh more victims of the Bhopal gas leak are to be paid an interim relief. We are also seeking funds to provide working-capital loans to certain PSUs pending their consideration by the BIFR. The technical supplementaries matched by corresponding receipts or savings include a large transfer to the National Renewal Funds, assistance to PSUs for financing voluntary retirement schemes and investments for certain public sector projects. Nine token grants have also been presented.

Madam, I have taken note of many points raised here by hon. Members. I would like to deal with them.

श्री शंकर दयाल सिंह: मंत्री के दौरे पर जो आपने 19.64 करोड़ रुपये रखे हैं इसको क्यों इतना बढ़ा रहे हैं?

SHRI SHANTARAM POTDUKHE: Madam, Dr. Shankar Dayal Singh, while initiating the discusion, has mentioned about Dunkel. I think it is listed in today's business. The Commerce Minister has gone on record saying that it would be discussed in Parliament and then a decision would be taken. The hon. Member will be having a chance to discuss the matter when the Dunkel Draft comes up for the consideration of this hon. House.

[Shri Shantaram Potdukhe]

The second point he has made is about the fertilizer subsidy. As you know, Madam, the issues were gone into by Joint Parliamentary Committee. The price adjustments, decontrol and assistance to small farmers are based on its recommendations. It is not correct to say that these are dictated by the IMF or the World Bank. We have also taken some steps.. *(Interruptions)*.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Are you going to give further concenssions to farmers by reducing fertiliser prices? That is the point.

SHRI SHANTARAM POTDUKHE: ....to mitigate the impact on farmers. We have provided Rs. 340 crores to mitigate the impact of price de-control of some types of fertilizers. The Government is already providing Rs. 500 crores to assist small farmer to make necessary investment.

Madam, Shri Sahu and other have made some points regarding employment and the poor. The policy and the procedural reforms that are taking place are intended to exploit the vast potential for growth in our country. Without this, much higher public investment in the sector most relevant to employment generation and poverty alleviation would not be possible. The thrust of the Eighth Plan is on agriculture, rural development, education and health. Our economy must generate resources to finance the Plan if its objectives are to be achieved.

Shri Ashis Sen made a point regarding assistance to the PSUs. Inorder to meet the needs of the public sector undertakings even in the case of sick units which are being considered by the BIFR and the Tripartite Committee, in these supplementaries themselves, we are proposing to give non-plan assistance for their immediate requirement. Mr. Sen has also referred to the Public Distribution System and the fair price shops in his speech. The Ministry of Civil Supplies has held detailed discussions with the State Governments and a scheme to revamp the Public Distribution System has been launched in order to take the PDS scheme to the remotest areas. The supplementary proposes Rs. 10 crores to strengthen the reach of this system through higher assistance for rural godowns and mobile vans.

Mr. Kamal Morarka has been very eloquent in his speech and while listening to him, he almost mesmerized everybody. I must tell him that I have carefully.

SHRI V. NARAYANASAMY: Mr. Yashwant Sinha, at least, the Minister is speaking. You had not spoken a word when you were the Finance Minister and got the Bill passed without sptaking. *(Interruptions)*

SHRI SHANTARAM POTDUKHE: I have carefully noted the views of Shri Morarka. On the Balance of Payments, exports are, to some extent, import-related. It is also true that in spite of recession abroad and the break-up of the Soviet Union, exports have picked up. I agree that the growth has been slow and we need faster growth. But I don't think that the increase that we have seen would have taken place in any case, as he says. However, as I have said earlier I have taken note of his views. I don't wish to take much time of this House. I have noted the points made by hon. Members. I would respond to them. I request this House to return the Finance Bill to Lok Sabha.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

> "That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the year 1992-93, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We shall not take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 and 3 and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI SHANTARAM POTDUKHE: Madam, I beg to move:

"That the Bill be returned."

The question was put and the motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, we would take up the Constitution (Seventy-Second Amendment) Bill, 1991 and the Constitution (Seventh-Third Amendment) Bill, 1991. I ask Mr. Venkat Swamy to move the Constitution (Seventy-Second Amendment) Bill, 1991.

I. THE CONSTITUTION (SEVENTY-SECOND AMENDMENT) BILL, 1991

II. THE CONSTITUTION (SEVENTY-THIRD AMENDMENT) BILL, 1991

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI G. VENKAT SWAMY): Madam Chairman, Sir,...

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV (Maharashtra): Sir, please address her as 'Madam', not 'Sir'.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Never mind.

SHRI G. VENKAT SWAMY: It is a slip of the tongue, I am sorry.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: Madam, sometimes people think you to be 'Sir'.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We would have to make a constitutional amendment whether I am 'Madam' or 'Sir'

SHRI G. VENKAT SWAMY: Madam, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Constitution of India, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

I want to say something, Sir, regarding this Bill.... (*Interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Never mind. Never mind.

श्री जी० वेंकटस्वामी : अगर आप इजाजत दें तो मैं हिन्दी में बोलूं ।

SHRI V. GOPALSAMY (TAMIL NADU): If he has started making his speech in English, why is he switching over to Hindi? That is very wrong.

उपसभापति : उनको बोलने दीजिये । हिन्दी में बोलिये उसमें सर और मैडम का चक्कर नहीं होता ।

SHRI V. GOPALSAMY: Because he addressed the Chair as 'Sir', he switched over to Hindi... (*Interruptions*)...

उपसभापति : अगर वे हिन्दी में बोलना चाहते हैं तो आप क्यों ऐतराज कर रहे हैं ?

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : हिन्दी हमारी राष्ट्र-भाषा है, हम हिन्दी में सुनना चाहते हैं ।

उपसभापति : इसमें लड़ाई-झगड़ा नहीं होगा ।

We are not discussing Hindi or English. बोलिये, आप जरूर हिन्दी में बोलिये ।

श्री जी० वेंकटस्वामी : मैं इस 72वें अमेंडमेंट बिल, जो अभी-अभी लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में आया है,